Daily
THE PHOTON NEWS
सच के हक में...
द फोटोन न्यूज Published from Ranchi
Ranchi • Saturday, 24 August 2024 • Year : 02 • Issue : 216 • Ranchi Edition • Page : 12 • Price : ₹3 • www.thephotonnews.com
E-Paper : epaper.thephotonnews.com

झारखण्ड सरकार
GOVERNMENT OF JHARKHAND

स्व. बिनोद बिहारी महतो की वीर भूमि उत्तरी छोटानागपुर की लाखों बहनों को

खुशियों का उपहार

झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत

श्री हेमन्त सोरेन
माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड

सम्मान राशि का करेंगे हस्तांतरण

24 अगस्त, 2024 | अपराह्न 12:30 बजे से
सिंदूर मैदान, हजारीबाग

उत्तरी छोटानागपुर (रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद और बोकारो)
की सभी बहनों का समारोह में स्वागत है

- 46 लाख से अधिक निबंधन
- अब तक 43 लाख बहनों का आवेदन स्वीकृत
- 31 अगस्त से पहले सभी बहनों के खातों में होगी एक हजार रुपये की सम्मान राशि (पहली किस्त)
- सितंबर से हर महीने की 15 तारीख को हर बहन के खाते में पहुँचेगी सम्मान राशि

झारखण्ड मुख्यमंत्री
मंईयां सम्मान योजना

हर बहना को हर साल ₹ 12 हजार

हेमन्त सोरेन
मुख्यमंत्री, झारखण्ड

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार

BRIEF NEWS

कांग्रेस ने डॉ. रामदयाल मुंडा की मनाई जयंती

RANCHI : शुक्रवार को पद्मश्री सह पूर्व सांसद डॉ. रामदयाल मुंडा की जयंती प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में मनायी गयी। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने डा. मुण्डा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें झारखंड का सांस्कृतिक विभूति बताया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नाची से बांची को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाने वाले डा. मुंडा ने झारखंड की संस्कृति को विश्व पटल पर पहचान दिलाया।

युवाओं की आवाज दबा रही हेमंत सरकार : आजसू

RANCHI : शुक्रवार को रांची के मोरहाबादी में प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर पुलिस कार्रवाई पर आजसू पार्टी के केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉ. देवशरण भगत ने कहा कि प्रदर्शनकारी युवाओं पर लाठी और आंसू गैस चलना अत्यंत निंदनीय है। इस दौरान कई युवा घायल भी हुए हैं। हेमंत सरकार अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाने पर आमादा है। यह लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या के समान है। भगत ने कहा कि सरकार ने युवाओं को रोकने के लिए रात में ही कटीले तारों के साथ जगह-जगह पर घेराबंदी कर दी थी और राज्य के अलग अलग हिस्से से रांची आ रहे युवाओं को रोका जा रहा था।

शिक्षा मंत्री के साथ पारा शिक्षकों की बैठक 28 को

RANCHI : शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम के साथ रांची पारा शिक्षकों (सहायक अध्यापकों) को वेतनमान के समतुल्य मानदेय बढ़ोतरी के लिए 28 अगस्त को बैठक होगी। इस बैठक में सहायक अध्यापकों के 10 प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस दौरान वेतनमान, ईपीएफ, कल्याण कोष, अनुकंपा पर नौकरी समेत केस मामले पर निर्णय लिए जाएंगे। मंत्री के साथ 14 अगस्त को भी बैठक हुई थी, लेकिन अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका था। शिक्षा विभाग 2000 रुपए बढ़ोतरी करने को तैयार था, लेकिन पारा शिक्षक पांच से छह हजार मानदेय बढ़ोत्तरी की मांग कर रहे थे।

आरपीएफ ने हटिया स्टेशन से जब्त की शराब

RANCHI : रेलवे सुरक्षा बल ने हटिया रेलवे स्टेशन से भारी मात्रा में शराब जब्त किया है। आरपीएफ उपनिरीक्षक दीपक कुमार ने शुक्रवार को बताया कि रांची मंडल के आरपीएफ कमांडेंट पवन कुमार के निर्देश पर रांची मंडल में शराब के धरपकड़ के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में हटिया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या तीन पर ट्रेन नंबर 18624 (हटिया-इस्लामपुर एक्सप्रेस) से चेकिंग के दौरान कोच नंबर एच-01 के सामने बैठने वाली कुर्सी के नीचे एक प्लास्टिक बैग रखा हुआ था, जिसमें चेक करने पर रॉयल स्टैग की 20 शराब की बोतल बरामद की गई।

डीजीपी से शिकायत के बाद नाबालिग बरामद, अपहर्ता अरेस्ट

आज कोर्ट में किया जाएगा पेश, अपहरण मामले में पिठोरिया थाना प्रभारी पर लापरवाही का लगाया गया है आरोप

थानेदार बोले- मुझपर लगाए गए आरोप बेबुनियाद, प्रेम प्रसंग से जुड़ा है मामला, आरोपी को पहले भी भेजा गया था जेल

SUHAIB @ RANCHI

रांची के पिठोरिया थानेदार के खिलाफ डीजीपी, डीआईजी व एसएसपी रांची से शिकायत की गई है। आरोप लगे हैं कि एक 16 वर्ष की नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में थानेदार और कांड के अनुसंधानकर्ता अभियुक्तों को ही संरक्षण दे रहे।

इसे लेकर नाबालिग के पिता ने शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा है कि उनकी बेटी को रहमतुल्लाह अंसारी सहित सात लोगों ने मिलकर बीते 24 जून को घर का एस्बेस्टस हटाकर गलत नियत से अपहरण कर लिया। इसे लेकर पिठोरिया थाना कांड संख्या 95/2024 दर्ज कराया है। इस मामले में थाना प्रभारी ने प्राथमिकी दर्ज करने में टालमटोल किया, न्यायालय के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज हुई। लेकिन प्राथमिकी दर्ज करने के बाद अपहताओं के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इससे अपहताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है और वे पीड़ित पिता को लगातार केस उठाने की धमकी दे रहे। नाबालिग बेटी फिलहाल अपहताओं के ही चंगुल में है। थानेदार से बेटी को बरामद करने व अभियुक्तों पर कार्रवाई का बार-बार अनुरोध करने पर उल्टे फटकार लगा रहे और झूठे केस में फंसाने की बात कह रहे। इधर, डीजीपी से शिकायत के बाद शुक्रवार शाम पुलिस हरकत में आई और नाबालिग लड़की को सकुशल बरामद कर लिया गया। वहीं मुख्य अपहर्ता रहमतुल्लाह अंसारी को दबोच लिया गया है।

पिठोरिया थाना परिसर में बरामद नाबालिग लड़की व गिरफ्तार अपहर्ता।

- घर का एस्बेस्टस हटाकर नाबालिग को गलत नीयत से किडनैप करने का एलिगेशन
- सात नामजदों पर दर्ज की गई थी एफआईआर
- पीड़िता के पिता को ही फटकार लगा रही थी पुलिस
- थाने में अपहर्ता से चल रही पूछताछ

> मुझपर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। मामला प्रेम प्रसंग का है। इस मामले में एक महीना पहले भी एफआईआर हुआ था। जिसमें लड़का जेल गया था, जमानत पर जेल से छूटने के बाद उसी लड़के के साथ लड़की दोबारा भाग गई। इस मामले में दोबारा मामला दर्ज किया गया। लड़की को बरामद कर लिया गया है। लड़के को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ चल रही है। शनिवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा।
>
> **गौतम कुमार रॉय**
> **थाना प्रभारी, पिठोरिया**

नाबालिग दोबारा अगवा पुलिस बोली, बार-बार बरामद करना मेरा काम नहीं

शिकायतकर्ता महमूद आलम का कहना है कि उनकी नाबालिग बेटी को दोबारा अगवा किया गया है। इस वजह से पुलिस कह रही कि बार-बार मेरा यही काम है, क्या। जबकि नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में कानूनी सख्त हैं। इसपर संवेदनशील होकर कार्रवाई करने के दिशा-निर्देश हैं। गौरतलब है कि इससे पूर्व दिनांक 10.05.2024 को उपरोक्त अभियुक्तों ने ही अपहरण कर लिया था। इस बाबत भी पिठोरिया थाना कांड संख्या-61/2024 दर्ज कराया गया था।

राज्य सरकार व नगर निगम को एक्शन प्लान बनाने का निर्देश

तालाबों पर अतिक्रमण करने वालों पर शीघ्र करें कार्रवाई : हाईकोर्ट

PHOTON NEWS RANCHI : झारखंड हाई कोर्ट जलाशयों के आसपास हो रहे अतिक्रमण पर सख्त है। हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण राय की खंडपीठ ने शुक्रवार को धुर्वा डैम, गेतलसूत डैम, कांके डैम और हरमू नदी समेत अन्य जलाशयों पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिया है। कोर्ट ने तीन सप्ताह में अतिक्रमण हटाने को लेकर वृहद अभियान चलाने का निर्देश दिया है। साथ ही अदालत ने राज्य सरकार और रांची नगर निगम को इस संबंध में एक्शन प्लान बनाने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि लगातार ग्राउंड वाटर के नीचे जाने की वजह से हम रिजर्व वाटर बॉडी पर आश्रित हो रहे हैं। ऐसे में यदि यह भी अतिक्रमण का शिकार हो जाएंगे तो सप्लाई वॉटर का विकल्प भी समाप्त हो जाएगा और भविष्य में हमें एक गहरे जल संकट से जूझना होगा। इसलिए जरूरी है कि इनके अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई हो। रांची के बड़ा तालाब और जिले के आसपास के जल स्रोतों को संरक्षित करने व इसमें हो रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। जनहित याचिका में कहा गया है कि बड़ा तालाब, कांके डैम और धुर्वा डैम की सैकड़ों एकड़ जमीन अतिक्रमणकारियों ने हड़प ली है और वहां मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है।

लैंड स्कैम : बिपिन सिंह ने दायर की जमानत अर्जी

जमीन घोटाला मामले में आरोपी बिपिन सिंह ने रांची पीएमएलए (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट में अपनी जमानत के लिए गुहार लगाई है। ईडी ने बिपिन सिंह को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े लैंड स्कैम केस में 24 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। बिपिन की जमानत अर्जी पर फिलहाल सुनवाई नहीं हुई है। इस केस से जुड़े अन्य अभियुक्तों को बेल देने से रांची पीएमएलए (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट इनकार कर चुका है।

चाईबासा में मनरेगा घोटाला मामला

ईडी से हाईकोर्ट ने मांगी अपटूडेट स्टेटस रिपोर्ट

चाईबासा में मनरेगा घोटाले मामले में दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। मामले में कोर्ट ने ईडी से दो सप्ताह में इस मामले में दर्ज ईसीआईआर केस की अपटूडेट स्टेटस (अब तक की जांच) की रिपोर्ट मांगी है। पिछली सुनवाई में ईडी की ओर से बताया गया कि मामले में दर्ज ईसीआईडी में अनुसंधान जारी है। इससे पहले सरकार की ओर से कोर्ट को बताया कि मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) में दर्ज 14 केस में जांच पूरी कर ली है, 13 केस में आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। प्रार्थी का जो आग्रह याचिका में था, वह पूरा हो चुका है इसलिए याचिका निष्पादित की जाए। वही प्रार्थी की ओर से मनरेगा घोटाला में चाईबासा के तत्काल डीसी के श्रीनिवासन की भूमिका पर सवाल उठाया गया। जिस पर कोर्ट ने कहा कि ईडी इस मामले की जांच कर रही है। दरअसल, चाईबासा में मनरेगा घोटाला कि सीबीआई जांच को लेकर मतलूब आलम की जनहित याचिका की सुनवाई हाईकोर्ट में हुई।

क्या है मामला : प्रार्थी की ओर से की ओर से कोर्ट को बताया गया था वित्तीय वर्ष 2008-9, 2009-10, 2010-11 में चाईबासा में करीब 28 करोड़ रुपए का मनरेगा घोटाला हुआ है। इसे लेकर चाईबासा में पुलिस ने 14 एफआईआर दर्ज की थी। बाद में एसीबी ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चाईबासा में उक्त 3 वित्तीय वर्षों में मनरेगा कार्यों में अग्रिम राशि का भुगतान तो कर दिया गया था लेकिन कोई काम धरातल पर नहीं हुआ था। उस समय चाईबासा के डीसी के श्रीनिवासन थे। बता दें कि चाईबासा में मनरेगा में घोटाला की जांच को लेकर प्रार्थी ने वर्ष 2013 में जनहित याचिका दाखिल की थी, बाद में कोर्ट ने इस मामले को निष्पादित कर दिया था।

हेमंत सरकार के खिलाफ युवा आक्रोश रैली

भाजपा कार्यकर्ताओं को जहां तहां रोका, पुलिस से नोकझोंक

भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकती पुलिस। ● फोटोन न्यूज

PHOTON NEWS RANCHI : झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ निकाली गई युवा आक्रोश रैली में शामिल होने के लिए रांची आ रहे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के कार्यकर्ताओं को राजधानी से पहले जहां-तहां रोक दिया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं को जहां रोका गया, उन्होंने वहीं पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन वाली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। राजधानी रांची के बीआईटी थाना क्षेत्र के रिंग रोड गोलंबर नेवरी चौक पर पुलिस ने 7 बसों को रोक दिया। इससे नाराज मेसरा मंडल के भाजपा कार्यकर्ता पुलिस के साथ उलझ गए। पुलिस और भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं की नोंकझोंक भी हुई। पलामू और लातेहार जिले से आ रहे भाजपा कार्यकर्ताओं के वाहनों को रातू चट्टी में पुलिस ने रोक दिया। नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने वहीं पर वाहनों से उतरकर हेमंत सोरेन सरकार एवं स्थानीय प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी शुरू कर दी। सिल्ली से आ रहे वाहनों को अनगड़ा में रिंगरोड के समीप पुलिस ने रोक दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने वहीं पर सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। ओरमांझी में भी बैरिकेडिंग लगाकर भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की गई। यहां पर नाराज भाजपा और भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने जबरन बैरिकेडिंग हटा दिया और रांची की ओर चल पड़े।

महिलाओं को सशक्त करना मुख्य उद्देश्य : एल खियांग्ते

महिला पुलिस सम्मेलन का उद्घाटन करते मुख्य सचिव व अन्य। ● फोटोन न्यूज

PHOTON NEWS RANCHI :

- दो दिवसीय महिला पुलिस सम्मेलन का मुख्य सचिव ने किया उद्घाटन

शुक्रवार को डोरंडा स्थित जैप वन स्थित शौर्य सभागार में दो दिवसीय महिला पुलिस सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य सचिव एल खियांग्ते ने दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर राज्य में पहली बार महिला पुलिस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। मौके पर गृह सचिव वंदना डाडेल, डीजीपी अनुराग गुप्ता, एडीजी सुमन गुप्ता के अलावा कई पुलिस अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त करना और महिला नागरिकों के लिए पुलिसिंग को अधिक बेहतर बनाना है। एक महिला पुलिस अधिकारी की उपस्थिति से महिलाएं अपनी समस्याओं को बिना हिचकिचाहट के साझा करने के लिए प्रोत्साहित हों। महिला अधिकारी की जिम्मेदारी में कोई अपनी समस्याओं को स्वतंत्र रूप से बताएं।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूर्ववत रहेगी कार्यरत :केशव महतो

RANCHI : प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूर्ववत कार्यरत रहेगी। आवश्यकता अनुसार उसमें सक्रिय कार्यकताओं एवं नेताओं को शामिल किया जाएगा तथा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने वालों को समीक्षा कर संगठन हित में निर्णय लिया जाएगा। ये बातें शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने संवाददाता सम्मेलन में कही। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर कार्यकताओं से संवाद के लिए संवाद आपके साथ कार्यक्रम के तहत स्वयं जिलों का भ्रमण करेंगे और इस क्रम में जिला पदाधिकारी, प्रखंड अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष और प्रमुख कांग्रेस नेताओं के साथ संगठन एवं आगामी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि चुनावी बिगुल बज चुका है,सरकार द्वारा किए गए कार्यों को संगठन के माध्यम से जमीनी स्तर पर जनता के बीच पहुंचाना आवश्यक है।

कनहर बराज के काम में देरी पर हाईकोर्ट नाराज

PHOTON NEWS RANCHI :

- पानी की समस्या से जूझ रही पलामू व गढ़वा की जनता
- केंद्र सरकार ने अब तक इस काम के लिए नहीं दिया फंड

झारखंड हाईकोर्ट ने पलामू एवं गढ़वा में सिंचाई के लिए प्रस्तावित कनहर बराज परियोजना अब तक शुरू नहीं किए जाने पर नाराजगी जताते हुए मौखिक कहा कि इस परियोजना में देरी पर सरकार को जनता के समक्ष जवाब देना होगा।

पलामू एवं गढ़वा की जनता पानी की समस्या से जूझ रही है, वर्षों से वहां आकाल की स्थिति बनी रहती है। लंबे समय से कनहर बराज परियोजना के संबंध में प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया है। यहां तक कि कनहर बराज के लिए जमीन अधिग्रहण, वन भूमि का क्लीयरेंस, एनवायरमेंट क्लीयरेंस आदि का काम पूरा नहीं हुआ। राज्य सरकार के लचीले रुख के कारण केंद्र सरकार से फंड भी अब तक आवंटित नहीं हो सकी है। पहले राज्य सरकार को कनहर बराज के अधूरे काम को पूरे कर लेना चाहिए थे, फिर फंड के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाना चाहिए था। कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित कनहर बराज परियोजना के देरी का कारण बताने के साथ-साथ कनहर बराज प्रोजेक्ट को लेकर फॉलो अप एक्शन (अब तक की कार्रवाही) 2 सप्ताह में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मौखिक कहा कि वर्ष 2010 में भी राज्य सरकार की ओर से इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 5 साल का समय मांगा गया था।

डोबो पुल पर प्रशासनिक पदाधिकारियों से झड़प

JAMSHEDPUR : भाजपा कार्यकताओं का हुजूम 23 अगस्त को रांची जा था, लेकिन उन्हें जिलों की हर सीमा पर रोका गया। इसकी शुरूआत मेरीन ड्राइव स्थित डोबो पुल पर हुई, जहां भाजपा के जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा, पूर्व जिलाध्यक्ष अभय सिंह, दिनेश कुमार आदि की प्रशासनिक पदाधिकारियों से तीखी झड़प हुई। सुधांशु ओझा की पहले पुलिस अधिकारियों, फिर वहां मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात जिला परिवहन पदाधिकारी धनंजय से तीखी बहस हुई। सुधांशु ओझा ने बताया कि भाजपा कार्यकताओं को प्रशासन द्वारा विभिन्न स्थानों पर वाहन चेकिंग के नाम पर रोका गया। प्रत्येक 100-200 मीटर की दूरी पर बड़ी गाड़ियों को वाहन चेकिंग के नाम पर रोक दिया जा रहा है।

पूर्व सीएम व सांसद को भी पुलिस ने रोका, बहस

CHAIBASA : भाजपा युवा मोर्चा द्वारा रांची में आयोजित युवा जन आक्रोश रैली में जा रहे पूर्व मुख्यमंत्री मधुकोड़ा और पूर्व सांसद गीता कोड़ा सहित भाजपा कार्यकताओं को पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा स्थित हाथी चौक और टाटा कॉलेज मोड़ पर रोक दिया। इस दौरान कोड़ा दंपती ने जांच को लेकर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यह पहली बार हो रहा है। यह हेमंत सरकार की डर का संकेत है। इस दौरान कोड़ा दंपती ने खुद वीडियो बनाकर रोकने वाले पुलिस अधिकारियों से पूछा कि क्या उनके पास इन्हें रोकने का कोई आदेश है, अगर है तो दिखाएं। जांच के नाम पर आप लोग सिर्फ लोगों को परेशान कर रहे हैं। थोड़ी बहस के बाद उन्हें जाने दिया गया।

10वीं पास वाले अभ्यर्थी नौकरी में, अब मास्टर डिग्री वाले भी लगा रहे दौड़

झारखंड में 44 साल बाद हो रही उत्पाद सिपाही की भर्ती

PHOTON NEWS RANCHI : देश में सरकारी नौकरी पाने की चाहत तकरीबन हर युवाओं की होती है। झारखंड इससे अछूता नहीं है। खनिज और वन्य संपदा से भरपूर इस पठारी राज्य में सरकारी नौकरियों की स्थिति यह है कि अपनी मंजिल हासिल करने के लिए कई युवाओं की नौकरी पाने की उम्र ही गुजर जाती है और फिर सारी जिंदगी वे पछताते रहते हैं। फिलहाल सरकार ने तकरीबन 44 साल बाद उत्पाद सिपाही के पद के लिए भर्तियां शुरू की है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उत्पाद विभाग में सिपाही पद के लिए योग्यता केवल 10वीं पास है, लेकिन यह नौकरी हासिल करने के लिए मास्टर डिग्रीधारी युवा भी दौड़ लगा रहे हैं। बता दें कि सरकार ने उत्पाद सिपाही के लिए 583 पदों पर बहाली कर रही है।

कब निकली थी उत्पाद सिपाही के पद पर अंतिम बार वैकेंसी : झारखंड में इससे पहले उत्पाद विभाग में नियुक्ति साल 2016 में हुई थी। लेकिन वो नियुक्ति सहायक अवर निरीक्षक और अवर निरीक्षक के पदों पर हुई थी। इसके बाद से इस विभाग में किसी भी प्रकार की कोई वैकेंसी नहीं आयी। उत्पाद सिपाही के लिए आखिरी बार वैकेंसी संयुक्त बिहार में साल 1980 में आयी थी। फिलहाल राज्य में उत्पाद सिपाही के कुल 622 पद सृजित हैं। जिसमें 589 पद रिक्त हैं। वहीं, सहायक अवर निरीक्षक के 105 में से 86 और अवर निरीक्षक के 125 में से 78 पद खाली हैं।

किस अत्याधुनिक तकनीक का किया जा रहा इस्तेमाल : झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इस बार उत्पाद सिपाही की भर्ती में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया है ताकि शारीरिक जांच और दौड़ में किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो सके। दौड़ की स्थिति का आकलन बारीकी से करने के लिए इस बार अभ्यर्थियों के पैर में आरएफआईडी यानि रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडेंटिफिकेशन डिवाईस लगाया गया है। जब अभ्यर्थी आरएफआईडी लगाकर जमीन पर बिछे मैट से होकर गुजरते हैं तो दौड़ की स्थिति का आकलन काफी बारीकी से हो पाता है। बताया जाता है कि रेडियो तरंगों के इस्तेमाल से सबसे पहले पहुंचने वाले अभ्यर्थी को ट्रैकिंग करने में चयन समिति को इससे सुविधा हो रही है।

क्या है न्यूनतम योग्यता

उत्पाद सिपाही के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास है। लेकिन इस नौकरी के लिए मास्टर डिग्री धारक भी आवेदन किए हुए हैं। सरकारी नौकरी की दिवानगी का आलम ये है कि लोग अपने स्वास्थ्य की चिंता किये बगैर दौड़ में हिस्सा लेते हैं। ताजा मामला पूर्वी सिंहभूम का है जहां एक युवक नौकरी पाने की जिद दम लगाकर दौड़ा। लेकिन इसके बाद उसकी हालत खराब हो गयी और उसकी मौत हो गयी।

विधानसभा चुनाव के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारियों का दो दिनी प्रशिक्षण शुरू

PHOTON NEWS RANCHI : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के तत्वावधान में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत विधानसभा चुनाव-2024 के निमित्त सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों का मोहराबादी स्थित सिविल सेवा अधिकारी संस्थान में दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुक्रवार को शुरू हुआ। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से प्रशिक्षक (रिसोर्स पर्सन) के रूप में नामित पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आरिज आफताब भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने झारखंड के पदाधिकारियों को चुनाव से जुड़े विभिन्न विषयों पर व्यावहारिक अनुभवों से अवगत कराया। इस दौरान उनके द्वारा विधि व्यवस्था को लेकर ध्यान में रखने वाली महत्वपूर्ण बातों का बिंदुवार प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने निर्वाचन के दौरान बुनियादी चुनाव प्रबंधन प्रणाली के बारे में भी विस्तृत रूप से जानकारी दी। दो प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले दिन के सत्र को संबोधित करते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा कि इस फेस टू फेस प्रशिक्षण के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के चुनाव संबंधी ज्ञान के संवर्धन तथा उनकी विभिन्न शंकाओं के समाधान का प्रयास किया जायेगा। उन्होंने चुनाव के क्रम में सम्भावित कुछ आम गलतियों (कॉमन एरर्स) पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए निर्देशित किया कि इन सब अप्रत्याशित गलतियों से बचने के लिए सभी को पहले से ही सजग रहना होगा ताकि निर्वाचन जैसे अति महत्वपूर्ण कार्य को जीरो एरर के साथ शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराया जा सके।

प्रशिक्षण में शामिल पदाधिकारी व अन्य। ● फोटोन न्यूज

Daily
THE PHOTON NEWS
सच के हक में...
द फोटोन न्यूज Published from Ranchi
Ranchi ● Saturday, 24 August 2024 ● Year : 02 ● Issue : 216 ● Ranchi Edition ● Page : 12 ● Price : ₹3 ● www.thephotonnews.com
E-Paper : epaper.thephotonnews.com

सुविचार

जो कविता का विकास होता है, वो रचना की अपनी शर्तों पर होता है।

-शमशेर बहादुर सिंह

Tamannaah Bhatia Exudes Divine...

SHARE

सेंसेक्स	:	81,086.21
निफ्टी	:	24,823.15

SARAFA

सोना	:	6,830
चांदी	:	91.07

(नोट : सोना 22 कैरेट प्रति ग्राम)

BRIEF NEWS

बबलू खान को ईडी का समन, 26 को बुलाया

RANCHI : झारखंड की राजधानी रांची से गिरफ्तार अलकायदा के संदिग्ध आतंकवादी डॉ इश्तियाक से जुड़े लेक व्यू हॉस्पिटल के संचालक बबलू खान को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने समन भेजा है। उसे 26 अगस्त को पूछताछ के लिए ईडी के रांची ऑफिस में बुलाया गया है। ईडी ने जो समन जारी किया है, उसमें बबलू खान से कहा गया है कि वह 26 अगस्त को दिन में 11 बजे जरूरी दस्तावेज के साथ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के ऑफिस पहुंचे। लेक व्यू हॉस्पिटल का लाइसेंस डॉक्टर इश्तियाक के नाम पर है। इश्तियाक को अलकायदा से संबंधित होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। डॉ इश्तियाक भारत के अलकायदा मॉड्यूल का लीडर बताया जा रहा है। एंटी टेररिस्ट स्क्वायड (एटीएस) की टीम ने डॉ इश्तियाक को 22 अगस्त को रांची के बरियातू से गिरफ्तार किया था।

उत्तराखंड में भूस्खलन में 4 नेपाली मजदूरों की मौत

DEHRADUN : उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश के दौरान रुद्रप्रयाग जिले में भूस्खलन की चपेट में आकर चार नेपाली मजदूरों की मृत्यु हो गई, जबकि हरिद्वार जिले में एक व्यक्ति उफनती नदी में नहाते समय बह गया। भारी बारिश से जगह-जगह भूस्खलन होने से बदरीनाथ, केदारनाथ और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भी यातायात के लिए बाधित हो गया। रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ के रास्ते में फाटा गांव में हेलीपैड के पास पहाड़ी से भूस्खलन होने से उसके मलबे के नीचे दबने से नेपाल के चार मजदूरों की मृत्यु हो गई। रुद्रप्रयाग के आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि गुरुवार मध्यरात्रि के बाद करीब 1.20 बजे हुई घटना की सूचना मिलने पर राज्य आपदा प्रतिवादन बल(एसडीआरएफ) की टीम मौके पर पहुंची और मलबे के अंदर से उनके शव बरामद किए।

केजरीवाल की जमानत याचिका पर 5 को सुनवाई

NEW DELHI : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की गई उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई पांच सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने सीबीआई को मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी। केजरीवाल को जवाब दाखिल करने के लिए दो दिन का समय दिया। बता दें कि केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था और धनशोधन मामले में निचली अदालत ने 20 जून को उन्हें जमानत दे दी थी। उच्च न्यायालय ने हालांकि निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी। उच्चतम न्यायालय ने 12 जुलाई को उन्हें धनशोधन मामले में अंतरिम जमानत दे दी थी।

भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने तोड़े अवरोधक, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले

मोरहाबादी बन गया रणक्षेत्र, लाठीचार्ज के साथ लगातार होती रही पानी की बौछार

युवा आक्रोश रैली

PHOTON NEWS RANCHI : शुक्रवार को भाजपा की युवा इकाई भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के कार्यकर्ताओं ने हेमंत सोरेन सरकार के कथित अन्याय और चुनावी वादों को पूरा न कर पाने के खिलाफ रांची के मोरहाबादी में आयोजित रैली के दौरान अवरोधक तोड़ डाले। इसके बाद पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। पानी की बौछारें छोड़ी। रैली में शामिल प्रदर्शनकारियों ने कार्यक्रम स्थल मोरहाबादी मैदान के पास स्थित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास की ओर कूच करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। आंसू गैस के गोले और पानी की बौछार के बाद भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं सहित पूरी भीड़ तितर-बितर हो गई। इसमें बोकारो नगर अध्यक्ष युवा मोर्चा विशाल गौतम समेत पांच भाजपा कार्यकर्ता घायल हो गए। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी जमकर पत्थरबाजी की, जिसमें पुलिस के सात जवान घायल हो गए। इन्हें अस्पताल ले जाने के लिए एंबुलेंस मंगाई गई। झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश समेत तमाम वरिष्ठ भाजपा नेता मैदान में ही धरने पर बैठ गए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने हेमंत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी के नारे भी लगाए।

पेज 03 पर युवा आक्रोश रैली व पेज 05 पर पढ़ें झामुमो के अधिकार मार्च की खबरें।

शुक्रवार को अवरोधक तोड़ने के बाद पुलिस के वाटर कैनन की बौछार से बचने की कोशिश करते भाजयुमो के सदस्य व इनसेट में प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़ता जवान।

- तितर-बितर हो गई भीड़, कई लोग घायल
- बीजेपी के पांच कार्यकर्ता जख्मी, एंबुलेंस से भेजा गया अस्पताल
- भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने भी की पत्थरबाजी पुलिस के सात जवानों को भी लगी चोट
- धरने पर बैठे बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, दीपक प्रकाश समेत तमाम वरिष्ठ नेता
- केवल सम्मेलन व बैठक के लिए ही जिला प्रशासन से मांगी गई थी इजाजत

रोकने से नहीं रुके कार्यकर्ता

मोरहाबादी मैदान में युवा आक्रोश रैली खत्म होने के बाद भाजयुमो के नेतृत्व में भाजपा नेता और कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही भाजपा समर्थकों ने सीएम आवास की ओर बढ़ने की कोशिश की, पुलिस ने उन्हें रुकने के लिए कहा। भाजपा समर्थक नहीं रुके। कई समर्थक कंटीले बैरिकेडिंग पर खड़े हो गए। प्रदर्शन करने लगे। जब भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जबरन सीएम आवास की ओर बढ़ने की कोशिश की, तो उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं ने दावा किया कि पुलिस के लाठीचार्ज करने से कई कार्यकर्ता घायल हो गए। पार्टी नेता अमर कुमार बाउरी ने कहा कि राज्य से झामुमो नीत गठबंधन को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। कोई भी हमें नहीं रोक सकता है।

लूट की खुली छूट

चौहान ने कहा, केवल एक डरा हुआ मुख्यमंत्री (हेमंत सोरेन) ही इस तरह की हरकतें कर सकता है। वह न तो सरकार चला पा रहे हैं और न ही अपनी पार्टी। हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल में राज्य में हत्याओं के 7,812 मामले, बलात्कार के 7,115, अपहरण के 6,937, दंगे के 8,792, लूट के 2,721, डकैती के 485 और अन्य अपराध के 2,73,261 मामले सामने आए हैं। आदिवासियों की जमीन घुसपैठिए हड़प रहे हैं, हर जगह खुली लूट मची हुई है। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार भाजपा से डरी हुई है, क्योंकि वह युवाओं से किए गए वादों को पूरा करने में विफल रही है दीपक प्रकाश ने कहा कि जनता ने सिंहासन खाली करो का आह्वान किया है।

आवाज दबाने का प्रयास

रैली का नेतृत्व भाजपा नेता सीपी सिंह कर रहे थे। भाजपा ने इस कदम को हेमंत सोरेन सरकार द्वारा किए गए अन्याय के खिलाफ भाजयुमो कार्यकताओं की आवाज दबाने का प्रयास करार दिया है। इसके साथ ही भाजपा ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में सरकार को बाहर का रास्ता दिखाए जाने में बमुश्किल दो महीने का ही समय बचा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झामुमो सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह कार्यकताओं की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है, जो उसके (झामुमो सरकार के) ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। चौहान ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) सरकार पर आरोप लगाया कि वह भाजयुमो कार्यकताओं को विभिन्न जिलों से रांची पहुंचने से रोक रही है और कई बसों को जब्त कर लिया गया है।

प्रशासन ने लगा दी थी धारा 144 नहीं मांगी गई थी रैली की अनुमति

भाजयुमो की युवा आक्रोश रैली से पहले प्रशासन ने राजधानी में निषेधाज्ञा लागू कर दी। अधिकारियों ने मोरहाबादी मैदान के पास शुक्रवार को पूर्वाह्न 11 बजे से रात 11 बजे तक किसी भी प्रदर्शन और सार्वजनिक बैठक पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिला प्रशासन ने मोरहाबादी मैदान के परिसर को छोड़कर इसके 500 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू कर रखी है। निषेधाज्ञा के तहत इस दायरे में सार्वजनिक सभाओं, रैलियों, धरना, प्रदर्शनों और पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध है। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि भाजयुमो कार्यकताओं ने निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया। रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने कहा, रैली के लिए अनुमति नहीं मांगी गई थी। उन्होंने सम्मेलन या बैठक के लिए अनुमति मांगी थी और इसे मंजूरी भी दे दी गई थी। मोरहाबादी मैदान की परिधि से आगे हमने निषेधाज्ञा लागू कर दी है, इसलिए किसी भी रैली की अनुमति नहीं है।

43 लोग थे सवार, 16 घायल, भर्ती

नेपाल में नदी में गिरी बस, 14 की गई जान

AGENCY NEW DELHI : शुक्रवार को मध्य नेपाल में भारत की नंबर प्लेट वाली एक बस राजमार्ग से पलट कर मार्सयांगडी नदी में गिरने गई। इस हादसे में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई। 16 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। यह बस गोरखपुर से चली थी और पोखरा से काठमांडू की ओर जा रही थी, तभी यह तनहुन जिले के आइना पहारा में राजमार्ग से पलट गई। बस पर उत्तर प्रदेश की नंबर प्लेट है और उसमें चालक और सहचालक सहित 43 लोग सवार थे। बस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। भारतीय दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, पोखरा से काठमांडू जा रही एक भारतीय पर्यटक बस में लगभग 43 भारतीय सवार थे।

मध्य प्रदेश में बस पलटने से 5 की मौत, 40 जख्मी

BHOPAL : गुरुवार की देर रात में भोपाल से हैदराबाद जा रही एक निजी बस महाराष्ट्र की सीमा से लगे मध्यप्रदेश के नवगठित पांढुर्ना जिले में पलट गई, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई और करीब 40 अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस के अनुविभागीय अधिकारी (एसडीओपी) बृजेश भार्गव ने फोन पर बताया कि रात करीब 10 बजे मोहित घाट पर डिवाइडर से टकराने के बाद बस पलट गई।

सेबी ने अनिल अंबानी को शेयर बाजार से 5 साल के लिए किया बैन

MUMBAI : मार्केट रेगुलेटर सेबी ने फंड की हेराफेरी के मामले में इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल अंबानी को शेयर बाजार से 5 साल के लिए बैन कर दिया है। अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुमार्ना भी लगाया गया है। उनके किसी भी लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर रहने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। सेबी ने रिलायंस होम फाइनेंस (आरएचएफएल) के पूर्व प्रमुख अधिकारियों समेत 24 अन्य एंटीटीज को भी शेयर मार्केट से बैन कर दिया है। इन पर अलग-अलग जुमार्ना लगाया गया है। रिलायंस होम फाइनेंस कंपनी को 6 महीने के लिए बैन किया है और 6 लाख रुपये का जुमार्ना लगाया है। सेबी की ओर से जारी 222 पेज के फाइनल फाइनल के मुताबिक, जांच में पता चला कि आरएचएफएल के अधिकारियों की सहायता से अनिल अंबानी ने पैसों की हेराफेरी की।

इनमें पूर्व प्रिंसिपल व पीड़िता के साथ डिनर करने वाले 4 डॉक्टर भी शामिल

कोलकाता रेप-मर्डर केस में मुख्य आरोपी समेत 6 का किया जाएगा पॉलीग्राफी टेस्ट

AGENCY KOLKATA : शुक्रवार को कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर का रेप-मर्डर करने वाले मुख्य आरोपी संजय रॉय को सीबीआई ने सियालदह की स्पेशल कोर्ट ने पेश किया। कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब मुख्य आरोपी संजय रॉय समेत 6 का पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाएगा। इनमें कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के अलावा पीड़ित डॉक्टर के साथ 8 अगस्त की रात डिनर करने वाले 4 डॉक्टर भी शामिल हैं। सुनवाई के दौरान ही संजय पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए भी तैयार हो गया था। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को एक ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के विरोध में कोलकाता के डॉक्टर्स 15वें दिन भी हड़ताल पर रहे।

विरोध में 15वें दिन भी हड़ताल पर रहे कोलकाता के चिकित्सक

एजेंसी की जांच के घेरे में कई सवाल

डॉक्टर रेप-मर्डर केस की जांच कर रही सीबीआई की जांच के घेरे में कई सवाल हैं। सीबीआई इस बात की जांच कर रही है कि इस अपराध को बिना किसी बाधा के सेमिनार हॉल में अंजाम दिया गया। उस हॉल के दरवाजे का टॉवर बोल्ट टूटा हुआ मिला। शुरुआती जांच में पता चला है कि टॉवर बोल्ट टूटने के कारण दरवाजा कुछ समय से खराब था। सीबीआई यह भी पता लगाने की कोशिश में है कि क्या कोई दूसरा शख्स सेमिनार हॉल के बाहर तैनात था। इसकी पुष्टि के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। अधिकारी इसकी जांच भी कर रहे हैं कि जब घटना को अंजाम दिया जा रहा था।

पोर्न देखने का आदी था मुख्य आरोपी संजय

ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय के साइकोएनालिटिकल प्रोफाइल से कुछ बातें सामने आई हैं। सीबीआई के अधिकारी ने बताया है कि वह विकृत मानसिकता का व्यक्ति और पोर्नोग्राफी का आदी था। उसके फोन में कई अश्लील वीडियो भी मिले हैं। सीएफएसएल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कोलकाता पुलिस में वॉलेंटियर संजय की प्रवृत्ति जानवरों जैसी है। पूछताछ के दौरान भी उसे कोई पछतावा नहीं था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के पूरे घटनाक्रम को विस्तार से बताया।

वायु सेना की जांच में तकनीकी खराबी की पहचान करने पर होगा फोकस

सुखोई-30 से गिरी थी इजरायली बैलिस्टिक मिसाइल रैम्पेज

पोखरण फायरिंग रेंज

AGENCY NEW DELHI : अनजाने में राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज के नजदीक 21 अगस्त को एयर स्टोर के रिसाव की घटना में इजरायली एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल रैम्पेज भारतीय वायु सेना के लड़ाकू विमान सुखोई-30 से गिर गई थी। हालांकि, घटना की जांच के लिए वायु सेना ने आदेश दिए हैं, जिसमें संभवतः उस तकनीकी खराबी की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसके कारण मिसाइल दुर्घटनाग्रस्त हुई। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रोटोकॉल का आकलन भी किया जाएगा। वायु सेना ने पोखरण फायरिंग रेंज के पास इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा था कि तकनीकी खराबी के कारण एक लड़ाकू विमान से 'एयर स्टोर' का अनजाने में रिसाव हो गया। इस घटना की जांच के लिए आदेश देते हुए वायु सेना ने यह भी कहा था कि इस घटना में जान-माल के किसी नुकसान की खबर नहीं है।

भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रोटोकॉल के पालन का आकलन जरूरी

उच्च लक्ष्यों पर सटीकता से हमला

वायु सेना की ओर से जांच शुरू करने का त्वरित निर्णय इस घटना की गंभीरता को दशार्ता है। इस घटना की जांच भी शुरू हो गई है, क्योंकि इस तरह के शक्तिशाली हथियार के अनजाने में छोड़े जाने से इन उन्नत हथियारों की विश्वसनीयता और सुरक्षा प्रोटोकॉल के बारे में चिंताएं पैदा हो गई हैं। वैसे तो वायु सेना की जांच के बारे में आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, दुर्घटनाग्रस्त हुई रैम्पेज एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल थी, जो फ्रंटलाइन मल्टी-रोल फाइटर जेट सुखोई-30 एमकेआई में एयर स्टोर का हिस्सा थी।

2020 में खरीदी गई थीं ये मिसाइलें

भारत ने 2020 में चीन के साथ गतिरोध के दौरान अपनी मारक क्षमताओं को बढ़ाने के मकसद से इजरायली रैम्पेज मिसाइलों को खरीदा था। रैम्पेज को वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर उत्पन्न तत्काल परिचालन आवश्यकताओं के समाधान के रूप में देखा गया था। वायु सेना ने इसी साल अप्रैल में अपने रूसी लड़ाकू विमान बेड़े सुखोई-30 एमकेआई, मिग-29 और जगुआर लड़ाकू विमानों को लंबी दूरी की रैम्पेज सुपरसोनिक एयर-टू-ग्राउंड मिसाइलों को शामिल करके मजबूत किया है, जो 250 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम हैं। इस मिसाइल का इस्तेमाल इजरायली वायु सेना ने ईरानी लक्ष्यों के खिलाफ हाल के अभियानों में बड़े पैमाने पर किया था। वायु सेना मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत रैम्पेज मिसाइलों के उत्पादन की संभावना पर भी विचार कर रही है। यह घटना परीक्षण और रखरखाव प्रक्रियाओं की खामियों को भी दशार्ती है, खासकर जब रैम्पेज मिसाइल जैसे जटिल और परिष्कृत हथियारों से निपटना हो। हालांकि, जांच के नतीजों में रैम्पेज मिसाइलों की विश्वसनीयता पर फोकस होगा। घटना की गहन जांच करने के लिए भारतीय वायु सेना की प्रतिबद्धता यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण होगी कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न्यूनतम हों।

28 को चम्पाई के गढ़ में हुंकार भरेंगे हेमंत

RANCHI : झामुमो के तेज तर्रार नेता कोल्हान टाइगर के नाम से प्रसिद्ध पूर्व मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने झामुमो से खुद को अलग कर विरोधी तेवर अख्तियार करते हुए अलग पार्टी गठन करने का ऐलान कर दिया है। वहीं दूसरी ओर टाइगर के गढ़ में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गरजने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल मंत्री चंपाई सोरेन के गढ़ उनके गृह जिले में ही 28 अगस्त को झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है। जिसकी तैयारी सरायकेला जिला पुलिस प्रशासन द्वारा शुरू कर दी गई है। प्रमंडल स्तरीय इस कार्यक्रम में कोल्हान प्रमंडल की बहन-बेटियों को सीएम हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत राशि प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री के इस प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारी को लेकर उपायुक्त रविशंकर शुक्ला एवं पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुणायत ने गम्हरिया प्रखंड के रपचा स्थित फुटबॉल मैदान का निरीक्षण किया।

पीएम की यात्रा पर दुनिया भर की निगाहें

भारत-यूक्रेन के बीच चार समझौते, बढ़ेगा सहयोग

AGENCY NEW DELHI : शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की ऐतिहासिक यात्रा पर पहुंचे। मॉस्को की यात्रा के सिर्फ छह सप्ताह बाद हो रही उनकी इस यात्रा पर दुनिया भर की निगाहें हैं। इस दौरान वह यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ, रूस-यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर बातचीत की। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी और राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने चार समझौतों पर हस्ताक्षर किए। भारत और यूक्रेन के बीच कृषि, चिकित्सा, संस्कृति और मानवीय सहायता में सहयोग के लिए चार समझौते हुए है। बता दें कि यूक्रेन के 1991 में स्वतंत्र होने के बाद यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है।

- 1991 में यूक्रेन के स्वतंत्र होने के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा

बारिश के बीच नौसेना ने चलाया सर्च अभियान, नहीं मिला विमान का मलबा

जहां मिला शव, उसी के पास चला अभियान, संभावित इलाकों को किया गया चिह्नित

PHOTON NEWS JSR:
सोनारी स्थित एयरपोर्ट से 20 अगस्त को उड़ान भरने के बाद लापता हुए ट्रेनी विमान को चार दिन बाद भी नहीं खोजा जा सका है। शुक्रवार को नौसेना, एनडीआरएफ और स्थानीय मछुआरों ने चांडिल डैम में सर्च अभियान चलाया पर लापता हुए विमान का कुछ पता नहीं चल पाया है। हालांकि, इसके पूर्व गुरुवार को चांडिल डैम से कैप्टन जीत और ट्रेनी शुभ्रदीप का शव बरामद किया गया था, जिससे यह साफ हो गया कि विमान चांडिल डैम में ही है। शुक्रवार को सुबह से ही तेज बारिश शुरू हो गई थी, जिसके बीच नौसेना ने अभियान को बिना रोक तलाश जारी रखी।

सोनार यंत्र की मदद से संभावित जगहों कर किया सर्च : शुक्रवार सुबह 7 बजे नौसेना ने दो बोट की मदद से सर्च अभियान की शुरूआत की। हालांकि बारिश होने की वजह से नौसेना वापस लौटी और फिर बोट पर तिरपाल बांधकर सर्च अभियान फिर से शुरू किया। इसके बाद टीम इसके बाद टीम ने अंधेरा होने तक सर्च अभियान चलाया। टीम ने सोनार (साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग) यंत्र की मदद से संभावित इलाकों में विमान के मलबे की तलाश की। नौसेना के एक अधिकारी ने 'द फोटोन न्यूज' को बताया कि जिस जगह शव मिला है, उसके 2 से 3 किमी की परिधि पर सर्च अभियान चलाया गया। इस दौरान सोनार यंत्र की भी मदद ली गई। हालांकि विमान का मलबा नहीं मिला, पर कुछ सबूत जरूर मिले हैं। ऐसे जगहों को चिह्नित किया गया है। शनिवार को नौसेना सुबह से ही अभियान की शुरूआत करेगी। जब तक मलबा नहीं मिल जाता, तब तक अभियान जारी रहेगा।

उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही लापता हो गया था विमान : सोनारी स्थित जमशेदपुर एयरपोर्ट से मंगलवार दोपहर अल्केमिस्ट एविएशन का ट्रेनी विमान उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद ही लापता हो गया था। विमान में कैप्टन जीत और ट्रेनी पायलट शुभ्रदीप मौजूद थे। एविएशन कंपनी को पटमदा में विमान के इमरजेंसी लैंडिंग होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद बोड़ाम थाना क्षेत्र के भुइयांसिनान स्थित बाटुलुका गांव के पास सर्च अभियान भी चलाया गया था। हालांकि, देर शाम चांडिल के पियालडीह गांव के एक ग्रामीण ने विमान के चांडिल डैम में डूबने की सूचना दी थी, जिसके बाद चांडिल डैम में विमान की तलाश शुरू की गई।

चांडिल डैम में रेस्क्यू अभियान चलाते सेना के जवान ● फोटोन न्यूज

पार्वती घाट में हुआ शुभ्रदीप का अंतिम संस्कार

गुरुवार को चांडिल डैम में मिले ट्रेनी पायलट शुभ्रदीप दत्ता के शव का बिष्टुपुर स्थित पार्वती घाट में अंतिम संस्कार किया गया। शव मिलने के बाद शुक्रवार को सरायकेला में शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया। इसके बाद आदित्यपुर के इच्छापुर स्थित आवास से शवयात्रा निकाली गई। इस शवयात्रा में बस्तीवासियों के अलावा शुभ्रदीप के साथ ट्रेनिंग करने वाले ट्रेनी पायलट भी अंतिम यात्रा में शामिल हुए।

गैस सिलेंडर फटने से मां समेत दो बच्चे झुलसे

JAMSHEDPUR : जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत दाईगुटु तेली लाइन में किराए के मकान में रहने वाली गौरी देवी और उनके दो बच्चे गैस सिलेंडर फटने से झुलस गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी को इलाज के लिए तत्काल एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। इस घटना में गौरी देवी की पीठ झुलस गई है जबकि उनका दो साल का बेटा बाहुबली कुमार 80 प्रतिशत तक झुलस गया, वहीं 6 साल का बेटा सूरज कुमार भी 50 प्रतिशत तक झुलस गया है। गौरी देवी ने बताया कि वह पास ही एक दुकान से सिलेंडर में गैस भरवाकर आई थी। खाना बनाने के दौरान गैस लीक कर रहा था। सिलेंडर के ऊपर वाले हिस्से को जैसे ही ढीला किया, वैसे ही सिलेंडर फट गया।

भाजपा पर बरसे हेमंत चम्पाई पर साधी चुप्पी

अंकिता महतो को श्रद्धासुमन अर्पित करते सीएम हेमंत सोरेन ● फोटोन न्यूज

JAMSHEDPUR : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को शहर आए थे। यहां वे भाजपा के खिलाफ तो खूब बरसे, लेकिन निवर्तमान मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन के झामुमो से अलग होने की बात पर चुप्पी साध ली।

चम्पाई के झामुमो से अलग होने के बाद पहली बार हेमंत सोरेन जमशेदपुर आए थे। सोनारी में पूर्व सांसद सुनील महतो की पुत्री अंकिता महतो की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे हेमंत ने कहा कि यह शोक की घड़ी है, ऐसे में राजनीतिक प्रतिक्रिया देना उचित नहीं होगा। हेमंत ने चम्पाई सोरेन के मुद्दे पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से परहेज किया। हालांकि, उन्होंने यह जरूर कहा कि चम्पाई से उनकी कोई नाराजगी नहीं है और वर्षों पुराने रिश्तों में कटुता की कोई जगह नहीं होती है। उन्होंने कहा कि झामुमो एक परिवार की तरह है।

जिला, प्रखंड या पंचायत स्तर के कार्यकर्ता इस परिवार के सदस्य हैं। हम सभी सदस्यों व उनके परिजनों के बीच विपरीत परिस्थिति में खड़े रहते हैं। रांची में आयोजित भाजपा की आक्रोश रैली पर कहा कि जिनके खिलाफ पूरा देश खड़ा है, वही आज आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। यह भाजपा का एजेंडा रहा है।

समाचार सार

मानगो में जलमग्न सड़क पर फंसी स्कूली वैन

JAMSHEDPUR : मानगो के मोहल्लों और बस्तियों की जर्जर सड़कें बरसात में तालाब की शक्ल ले रही हैं। बदहाल सड़कों पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं, जो जलजमाव के कारण नजर नहीं आते। इस वजह से दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। मानगो नगर निगम के अंतर्गत रोड नंबर 15, ब्रह्मा पथ शुक्रवार को बारिश के कारण तालाब की शक्ल ले चुका था। पैदल चलने वाले तो किसी तरह आ-जा रहे थे, लेकिन कई वाहन फंस गए। इसी क्रम में इस सड़क पर एक स्कूल वैन फंस गई, जिसमें स्कूली बच्चे सवार थे। सभी राधा-कृष्ण के पोशाक में सजे थे। वैन उन्हें स्कूल से लेकर लौट रही थी। वैन फंस जाने के कारण बच्चे काफी डरे-सहमे थे। कुछ बच्चे इस दौरान रोते-बिलखते रहे। स्कूल वैन के पीछे मानगो नगर निगम का वाहन भी फंसा था। स्थानीय लोगों के प्रयास से अन्य वाहन लाकर बच्चों को उनके घर तक पहुंचाया गया। इस संबंध में मानगो नगर निगम के पदाधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन बात नहीं हो सकी।

डॉ. विजय सिंह गागराई कल करेंगे शक्ति प्रदर्शन

CHAKRADHARPUR : पीपुल्स वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव डॉ. विजय सिंह गागराई रविवार को शक्ति प्रदर्शन कर विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर सकते हैं। शुक्रवार को गागराई ने चक्रधरपुर के पोटका स्थित अपने आवासीय परिसर में संवाददाता सम्मेलन कर संगठन के आगामी कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 25 अगस्त को चक्रधरपुर के पोड़ाहाट स्टेडियम में चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र के उत्थान, विकास और नवनिर्माण के लिए परिचर्चा सह जनसभा की जाएगी। गागराई ने कहा कि हमारी संस्था 2017 से मानवसेवा कर रही है। इसके तहत चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र में 10 हजार से अधिक लोगों को कंबल बांटे गए। ग्रामीणों को पर्व त्योहारों के अवसर पर मांदर, साड़ी, धोती का वितरण किया। 25 अगस्त के बाद संस्था से इस्तीफा दूंगा। हो सकता है किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करूं और चुनाव लड़ूं। जनता की मांग है कि हर हाल में चक्रधरपुर विधासभा सीट से अगला विधानसभा चुनाव लड़ूं। इस मौके पर संस्था के सदस्य प्रदीप महतो, सरोज महतो, संतोष सिंहदेव, राहुल रंजन, रामराय सामड, वीर सिंह हांसदा, मरकूस गागराई, अनमोल प्रताप महतो, मंत्री सुंडी, जयपाल जामुदा, मुखिया महतो समेत अन्य मौजूद थे।

नए प्राचार्य डॉ. बीएन प्रसाद ने लिया प्रभार

JAMSHEDPUR : करनडीह स्थित एलबीएसएम कॉलेज में डॉ. बीएन प्रसाद ने नए प्राचार्य के रूप में योगदान दिया। इससे पूर्व डॉ. प्रसाद सरायकेला स्थित काशी साहू कॉलेज में प्राचार्य थे। अब तक कॉलेज की कमान संभाल रहे डॉ. अशोक कुमार झा ने उन्हें प्रभार सौंपा। इस अवसर पर प्रो. बिनोद कुमार, डॉ. विनय कुमार गुप्ता, डॉ. दीपंजय श्रीवास्तव, अनिमेष बख्शी, संजीव मुर्मू, सौरभ वर्मा, मिहिर डे, बिरेश चंद्र सरदार, पुनीता मिश्रा, ज्योति, प्रियंका सिंह, विनय कुमार, राजेश कुमार समेत कॉलेज के सभी शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित थे।

लोयोला के 'एजियोनरे' में चिन्मया ओवरऑल चैंपियन

लोयोला ऑडिटोरियम में रंगारंग कार्यक्रम के विजेता व अतिथि ● फोटोन न्यूज

JAMSHEDPUR : बिष्टुपुर स्थित लोयोला स्कूल में शुक्रवार को वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव 'एजियोनरे' का आयोजन किया गया। इसमें विद्याभारती चिन्मया विद्यालय ओवरऑल चैंपियन तथा कार्मेल जूनियर कॉलेज रनरअप रहा। इसमें शहर के 17 स्कूल ने भाग लिया था। स्कूल के प्रिंसिपल फादर विनोद फर्नांडीस ने स्वागत भाषण दिया। इसके बाद छात्र-छात्राओं ने स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में 2003 बैच के पासआउट एलुमिनी एवं फिल्म निर्देशक साजिद अली मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथि मिस यूनिवर्स झारखंड शताक्षी किरण थीं। साजिद अली ने अपने संबोधन में समग्र शिक्षा के लिए स्कूल की प्रतिबद्धता पर बल दिया, जिसमें पाठ्यक्रम में विभिन्न कौशलों और अनुभवों को एकीकृत करके संतुलित व्यक्तियों को पोषित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया । उन्हें फादर रेक्टर, प्रिंसिपल और फादर पायस (पूर्व प्रिंसिपल) ने सम्मानित किया। उसके बाद एजियोनरे 2024 का उद्घाटन हुआ।

सर्पदंश से 11 वर्षीय बच्चे की मौत

GHATSILA : बासाडेरा गांव के 11 वर्षीय किशोर चंदन महतो की मौत शुक्रवार को सर्पदंश से हो गई। घटना के संबंध में मृतक के पिता लकी चरण महतो ने बताया कि चंदन रात में घर के अंदर खटिया पर सोया हुआ था। अचानक पहाड़ी चित्ती सांप ने डंस लिया। सुबह लगभग 4 बजे पता चला कि चंदन को सांप ने डंस लिया है। बेटे को अचेतावस्था में पड़ोसी की मदद से बाइक पर लेकर अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया। वहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर घाटशिला पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

बिष्टुपुर फायरिंग मामले में हथियार के साथ चार गिरफ्तार, हथियार भी जब्त

PHOTON NEWS JSR:
बिष्टुपुर स्थित मारुति सुजुकी एरिना शोरूम में 17 अगस्त की शाम को अज्ञात अपराधियों ने फायरिंग कर पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी थी। इस घटना में शोरूम के शीशे से गोली आर-पार हो गई थी। हालांकि फायरिंग में किसी भी व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई और न ही कोई अन्य संपत्ति का नुकसान हुआ। घटना के बाद पुलिस ने शोरूम के मैनेजर के बयान पर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान ही पुलिस ने मामले में संलिप्त चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हथियार भी बरामद कर लिया है। एसएसपी किशोर कौशल ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। पुलिस शनिवार को मामले का खुलासा करेगी।

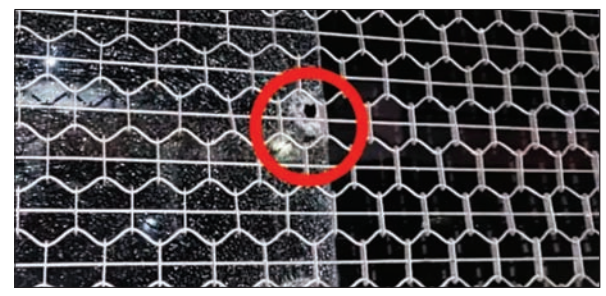

बिष्टुपुर के शोरूम के शटर में फायरिंग का निशान (फाइल फोटो)

रंगदारी के लिए चलाई थी गोली

घटना के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की। पुलिस ने शोरूम के मालिक से भी पूछताछ की, पर मालिक ने किसी से दुश्मनी या रंगदारी मांगे जाने की बात से इंकार किया। इसके बाद पुलिस ने घटना के दौरान शोरूम में मौजूद छह ग्राहक और कर्मचारियों से भी पूछताछ की, पर पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी की भी जांच की। इसके बाद पुलिस को एक सीसीटीवी में एक संदिग्ध नजर आया। संदिग्ध की पहचान कर पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। कड़ाई से पूछताछ करने पर संदिग्ध युवक ने फायरिंग की बात कबूल की और पुलिस को बताया कि उन्होंने अन्य लोगों से रंगदारी मांगने के लिए शोरूम के बाहर फायरिंग की थी।

भाजपा में शामिल हुए 'आप' नेता प्रेम कुमार व कांग्रेस के चंदन सिंह

रांची स्थित भाजपा के प्रदेश कार्यालय में बाबूलाल मरांडी व अन्य ● फोटोन न्यूज

PHOTON NEWS JSR:
आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपसंयोजक प्रेम कुमार व कांग्रेस नेता चंदन कुमार सिंह शुक्रवार को भाजपा में शामिल हो गए। रांची स्थित भाजपा के प्रदेश कार्यालय में इन्हें प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दल की सदस्यता दिलाई। ज्ञात हो कि प्रेम कुमार अन्ना आंदोलन के पहले दिन से जुड़ गए थे और आप के संस्थापक सदस्य थे। उन्होंने 11 अगस्त को ही आप की प्राथमिक सदस्यता छोड़ दी थी। वहीं चंदन कुमार सिंह कांग्रेस, इंटक व कांग्रेस सेवा दल के बिभिन्न पदों पर थे। प्रेम कुमार और चंदन कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से कहा कि आज से भाजपा मेरा परिवार है। हमें पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर एक समृद्ध झारखंड के लिए कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे।

कई कांग्रेसियों की हुई घर वापसी, हुआ स्वागत

CHAIBASA: कांग्रेस के पूर्व जिला महासचिव त्रिशानु राय, पूर्व सचिव संतोष सिन्हा, पूर्व नगर अध्यक्ष अजय कुमार, पूर्व प्रखंड सदस्य जुम्बल सुंडी, पूर्व जिला कार्यकारिणी सदस्य राकेश कुमार सिंह का प्रदेश नेतृत्व के अनुमोदन उपरांत घर वापसी हुई है। शुक्रवार को कांग्रेस जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर दास ने कांग्रेस भवन , चाईबासा में चारों को पार्टी में शामिल कराया। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष सन्नी सिंकु, अल्पसंख्यक उपाध्यक्ष जहांगीर आलम, प्रखंड अध्यक्ष सकारी डोंगो, अजीत कांडेयांग, चंद्रभूषण बिरुवा, शैली शैलेंद्र सिंकु, सुशील कुमार दास, संजय साव सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे।

कुलपति से मिला टाकू का शिष्टमंडल

JAMSHEDPUR : टीचर्स एसोसिएशन ऑफ कोल्हान यूनिवर्सिटी (टाकू) का शिष्टमंडल शुक्रवार को विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति सह प्रमंडलीय आयुक्त हरिकुमार केसरी से मिला। इस दौरान टाकू ने श्री केसरी को शिक्षकों की समस्याओं से अवगत कराते हुए, उसके समाधान को लेकर वार्ता की। शिक्षकों ने प्रभारी कुलपति के समक्ष वर्ष 2022 एवं उसके बाद नियुक्त शिक्षकों के वार्षिक वेतन वृद्धि, 2008 बैच के शिक्षकों की पदोन्नति, विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग द्वारा केंद्र व्यय, वीक्षकों एवं परीक्षकों का पारिश्रमिक, उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन का पारिश्रमिक महाविद्यालय को नहीं भेजे जाने आदि की मांगों से अवगत कराया। इस दौरान कुलसचिव डॉ. राजेंद्र भारती एवं वित्त पदाधिकारी डॉ. विनय कुमार कुमार सिंह उपस्थित थे।

वर्कर्स कॉलेज के छात्रों को दी गई एंटीरैगिंग सेल की जानकारी

छात्रों को रैगिंग से बचने के टिप्स देते वक्ता ● फोटोन न्यूज

JAMSHEDPUR : मानगो स्थित जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज में छात्र-छात्राओं के लिए शुक्रवार को एंटी रैगिंग जागरूकता कार्यक्रम किया गया। कॉलेज के एंटीरैगिंग सेल की को-ऑर्डिनेटर प्रो सुनीता गुड़िया की देखरेख में चले कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं का आत्मविश्वास बढ़ाया गया। सुनीता गुड़िया ने कहा कि कॉलेज में नए छात्र-छात्राओं से कभी-कभी सीनियर छात्र-छात्राएं रैगिंग या उनसे दुर्व्यवहार करते हैं। यह कभी भी और किसी भी शैक्षणिक परिसर के वातावरण के लिए सही नहीं है। कार्यक्रम में कॉलेज के प्राचार्य डॉ. एसपी महालिक, डॉ. जावेद इकबाल अंसारी, प्रो. सुभाष दास, प्रो. जावेद अख्तर अंसारी, डॉ. असफारूल हक एवं प्रो. नवनीत कुमार सिंह ने भी अपने विचार रखे।

झारखंडियों के खिलाफ हर साजिश का जवाब वोट से देगी जनता : जोबा

झींकपानी में कार्यकर्ताओं को संबोधित करतीं सांसद जोबा माझी ● फोटोन न्यूज

JHINKPANI : पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा सदर विधानसभा क्षेत्र के झींकपानी प्रखंड के विभिन्न गांवों में शुक्रवार को सिंहभूम की सांसद जोबा माझी का अभिनंदन हुआ। इस दौरान स्थानीय विधायक सह आदिवासी कल्याण सह परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा भी मौजूद रहे। कुदाहातु स्थित एसके होटल मैदान सांसद जोबा माझी ने लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए मतदाताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि जिस भरोसे के साथ उन्हें चुना गया है, उसे हर हाल में कायम रखेंगे। सांसद ने वर्तमान राजनीति परिदृश्य पर विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा पहले धर्म-जाति के नाम पर लड़ाने वाले अब परिवार को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन जनता सब साजिश समझती है। विपक्ष की हर साजिश का जवाब आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट के जरिए देना है। मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि राज्य की हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार राज्य को तेज गति से विकास के पथ पर ले जा रही है।

ट्रिब्यूनल ने कहा-अंचलाधिकारी का नोटिस जिला प्रशासन का मामला, प्रशासन देगा एनजीटी का हवाला तब करेंगे सुनवाई

भुइयांडीह के घरों को तोड़ने के मामले को एनजीटी ने नहीं सुना

PHOTON NEWS JSR :
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इंद्रानगर-कल्याण नगर के बस्तीवासियों का घर टूटने के विरूद्ध बस्तीवासियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता संजय उपाध्याय द्वारा दायर हस्तक्षेप याचिका इस आधार पर सुनने से इंकार कर दिया कि बस्तीवासियों का घर तोड़ने के लिए जमशेदपुर के अंचलाधिकारी द्वारा दी गई नोटिस का एनजीटी के प्रासंगिक मुकदमा से कोई संबंध नहीं है।

एनजीटी ने वरीय अधिवक्ता को सुनने के बाद कहा कि जमशेदपुर अंचलाधिकारी की नोटिस का न तो दलमा इको-सेंसिटिव जोन से इन घरों की दूरी का कोई संबंध है और न ही स्वर्णरेखा नदी तट से इनकी दूरी का कोई संबंध है। जमशेदपुर अंचलाधिकारी की यह नोटिस विशुद्ध रूप से ज़िला प्रशासन का मामला है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कार्यालय की फाइल फोटो

वरीय अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जमशेदपुर के तमाम अखबारों में प्रमुखता से खबर प्रकाशित हो रही है कि इंद्रानगर-कल्याण नगर के करीब 150 घरों को तोड़ने की नोटिस जिला प्रशासन ने एनजीटी के आदेश पर किया है तो एनजीटी की बेंच ने कहा कि इन घरों का उल्लेख एनजीटी के आदेशानुसार गठित संयुक्त जांच समिति के प्रतिवेदन में नहीं है। झारखंड सरकार के वन पर्यावरण विभाग की रिपोर्ट में भी इनका उल्लेख नहीं है। झारखंड सरकार के मुख्य सचिव ने अभी तक शपथ पत्र नहीं दिया है कि किनके घर तोड़े जाएंगे। एनजीटी ने बस्तीवासियों के अधिवक्ता संजय उपाध्याय की दलील पर कहा कि आगे कभी झारखंड सरकार के किसी प्रतिवेदन में अथवा मुख्य सचिव के शपथ पत्र में इन घरों को एनजीटी के निदेर्शानुसार तोड़ने की बात आएगी तो उस समय आप इस मामला को लेकर एनजीटी के सामने आने के लिए स्वतंत्र हैं।

सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता संजय उपाध्याय की बात को कोर्ट ने ध्यान से सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि पूर्वी सिंहभूम, ज़िला प्रशासन ने एनजीटी के आदेश का हवाला देकर इंद्रानगर- कल्याण नगर के घरों को तोड़ने की नोटिस दिया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि ऐसा होगा, तब हम आपकी बात जरूर सुनेंगे।

5 साल कुछ नहीं किया, अब क्रेडिट ले रहे सरयू राय : डॉ. अजय कुमार

JAMSHEDPUR : पूर्व सांसद सह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉ. अजय कुमार ने शुक्रवार को प्रेस बयान में कहा कि भुइयांडीह मामले में 5 साल कुछ न कर पाने वाले सरयू राय अब चुनाव के पहले क्रेडिट ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि भुइयांडीह के लोग 25 साल से नारकीय जिंदगी जीने को मजबूर थे। लोगों ने परिवर्तन के नाम पर सरयू राय का समर्थन किया था, लेकिन पिछले 5 वर्षों में विधायक सरयू राय द्वारा भुइयांडीह के कल्याणनगर, राधिकानगर, भुइयांडीह बस्ती में नागरिक सुविधा से संबंधित कोई काम नहीं किया गया। यह मैं नहीं, बल्कि मीडिया रिपोर्ट में छप रही खबरों में है। अगर विधायक द्वारा कुछ किया गया होता तो यह स्थिति नहीं होती। बस्ती के इन घरों में शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। इससे बड़ी शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती है।अब जबकि मेरे द्वारा क्षेत्र में जाकर निवासियों के मुद्दों को हल करने का प्रयास किया जा रहा है. तो विधायक की आंखें खुलीं और अब बस्ती में जाकर क्रेडिट ले रहे हैं। डॉ. अजय ने कहा कि शनिवार को इस मामले में पूरी जानकारी साझा करेंगे।

झामुमो का अधिकार मार्च, भाजपा पर निशाना

राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आयोजित किया कार्यक्रम, विपक्ष को दिया जवाब

RANCHI/JSR : झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से शुक्रवार को अधिकार मार्च का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया गया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित आक्रोश रैली के ठीक उलट सत्ताधारी दल ने अपने प्रदर्शन के जरिए मुख्य विपक्षी दल को निशाने पर लिया। भाजपा की नीतियों को झारखंड के लिए अहितकर बताया गया। पार्टी के नेताओं ने अपने संबोधन में कहा कि एक तरफ केंद्र की भाजपा सरकार झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा राजनीतिक प्रोपोगेंडा फैलाकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। हकीकत यह है कि राज्य की हेमंत सरकार सीमित संसाधनों में राज्यवासियों के हित में नित नए निर्णय ले रही है।

भाजपा की रैली राज्य को अशांत करने की कोशिश : महुआ

PHOTON NEWS RANCHI : झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने केंद्र सरकार के खिलाफ शुक्रवार को अधिकार मार्च निकाला। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक मार्च निकालने के बाद वहां झामुमो नेताओं ने एक जनसभा को संबोधित किया। राज्यसभा की सांसद महुआ माजी ने मोरहाबादी में आयोजित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की युवा इकाई भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) की युवा आक्रोश रैली को झारखंड को अशांत करने की कोशिश करार दिया।

रांची में झामुमो के अधिकार मार्च का नेतृत्व करतीं महुआ माजी ● फोटोन न्यूज

कोयला की रॉयल्टी का 1.36 लाख करोड़ नहीं दे रही केंद्र सरकार : राज्यसभा सांसद महुआ माजी ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) का आज का मार्च केंद्र सरकार के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार झारखंड के साथ खिलवाड़ कर रही है। सिर्फ कोयले की रॉयल्टी के 1.36 लाख करोड़ रुपए बकाया हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई बार केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वह पैसे राज्य सरकार को दिए जाएं। मैंने खुद राज्यसभा में इसका मुद्दा उठाया। लेकिन अब तक झारखंड को उसके हक के पैसे नहीं मिले हैं।

कोयले की रॉयल्टी से झारखंड के युवाओं को मिलेगा रोजगार : उन्होंने कहा कि अगर ये पैसे झारखंड सरकार को मिल जाएं, तो उस पैसे से यहां के तमाम युवाओं को रोजगार मिल सकती है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि झारखंड का अधिकार देने की बजाय केंद्र की भाजपा सरकार यहां के युवाओं को भड़का रही है। युवा आक्रोश रैली निकाल रही है।

केंद्र सरकार नहीं दे रही झारखंड का नैतिक अधिकार : रामदास

JAMSHEDPUR : झामुमो, केंद्रीय समिति के निर्देश पर पूर्वी सिंहभूम जिला समिति ने शुक्रवार को साकची में झारखंडी अधिकार मार्च निकाला, जिसमें केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया गया। आमबगान मैदान से जिला मुख्यालय तक निकले मार्च का नेतृत्व कर रहे जिला अध्यक्ष सह विधायक रामदास सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा झारखंड के हक एवं अधिकार को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता मोहन कर्मकार, पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां, शेख बदरुद्दीन, प्रमोद लाल, सुनील महतो, वीर सिंह सुरीन, सागेन पुर्ती, अरुण प्रसाद, महावीर मुर्मू, बब्बन राय, चंद्रावती महतो, फैयाज खान, सुराई टुडू, मिर्जा सोरेन, राजा सिंह, प्रधान सोरेन, सोमाय सोरेन, बुराई मरांडी, कान्हु सामंत, वकील हेंब्रम, राज लकड़ा, अजय रजक, विनोद डे, समद अंसारी आदि शामिल थे।

जमशेदपुर में प्रदर्शन करते झामुमो नेता

नक्सली बता पुलिस जवान व उनके भाई के घर में डकैती

घटना की जांच करती पुलिस की टीम व मौके पर जुटी भीड़ ● फोटोन न्यूज

PALAMU : मेदिनीनगर सदर थाना क्षेत्र सिंगरा के बजराहा में पुलिस जवान और उनके भाई के घर में भीषण डकैती हो गई। हथियार के बल पर 12 से 15 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। डकैत खुद को नक्सली बता रहे थे। घटना की सूचना मिलने पर सदर एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद एवं सदर थाना प्रभारी उत्तम कुमार राय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और छानबीन शुरू कर दी है। घटना गुरुवार रात के 12 बजे के करीब की है। पुलिस जवान संदीप राम के घर में डकैत लकड़ी की सीढ़ी के सहारे छत पर चढ़े थे उसके बाद पूरे परिवार को हथियार के बल पर बंधक बना लिया और घर में रखे जेवरात और नगद को लूट लिया। डकैतों ने संदीप राम के पिता को बंधक बनाया। बंधक बनाने के बाद डकैत पिता के माध्यम से संदीप के बड़े भाई का घर खुलवाया और लूटपाट की। संदीप राम के बड़े भाई लालसू राम ने शुक्रवार को बताया कि घर खुलवाने के बाद उन्हें हथियार के बल पर बंधक बना लिया गया था। डकैतों ने उनके हाथ पैर बांध दिए और घर के कमरे में बंद कर दिया था। बाद में डकैती उनके घर से नगद और जेवरात लेकर चले गए।

BRIEF NEWS

महिला ने फांसी लगाकर दी जान

GODDA : जिले के महगामा प्रखंड के हीर करहरिया गांव में शाहिस्ता खातून (30) ने दुपट्टा से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शाहिस्ता के शव को उनके घर के पास स्थित मवेशी घर में बांस से लटका पाया गया। पुलिस के मुताबिक, घटना की सूचना मिलने पर हनवारा थाने के प्रभारी अक्षय कुमार और एसआई भोलेनाथ भगत ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए गोड्डा सदर अस्पताल भेजा। मृतिका के पिता शाबिर अंसारी ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। उन्होंने कहा कि शाहिस्ता के पति मोजाहिद अंसारी ने उनकी बेटी के साथ हमेशा मारपीट की थी और हाल ही में भी उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया था।

हड़ताल पर गए पलामू निकायकर्मी

PALAMU : छह सूत्री मांगों को लेकर निकायकर्मी कर्मी शुक्रवार से अनिश्चितकाली हड़ताल पर चले गए। मेदिनीनगर नगर निगम, विश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद एवं हरिहरगंज के कर्मी भी हड़ताल में शामिल हैं। सारे कर्मी अपने अपने कार्यालय परिसर में मांगों के समर्थन में धरना देते नजर आए। कर्मियों की हड़ताल से कार्यालय कार्य के साथ-साथ सफाई कार्य पर बुरा असर पड़ेगा। नगर निगम मेदिनीनगर से जुड़े कर्मचारियों ने अपनी मांगों पर जोर डालने के लिए झारखंड लोकल बॉडीज इम्प्लाइज फेडरेशन के बैनर तले कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों की मांगों में निकाय में कार्यरत दैनिक एवं मानदेय कर्मियों की सेवा नियमित करने, निकायकर्मियों का वेतन भुगतान के लिए सरकार स्तर से शत-प्रतिशत आवंटन निर्गत करने, निकाय में सेवानिवृत होने वाले तमाम तरह की सेवानिवृत्ति लाभ, भुगतान सरकार अपने कोष से करें।

होमगार्ड जवानों को 2017 से मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन

DHANBAD : राज्य भर के होमगार्ड जवानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। उन्हें बढ़े हुए वेतन का लाभ 25 अगस्त 2017 से मिलेगा। इस मामले पर शुक्रवार को झारखंड उच्च न्यायालय ने आदेश जारी कर दिया है। न्यायाधीश एसएन पाठक की कोर्ट में अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया गया है। होमगार्ड जवानों की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता केएल जनजानिया , अभय कांत मिश्रा, झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता डीके चक्रवर्ती एवं अशोक सिंह ने बहस की।

यह आदेश दिया गया कि होमगार्ड जवानों को पुलिस कर्मियों के समकक्ष समान कार्य का समान वेतन का लाभ झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश की 25 अगस्त 2017 से ही देना है। इधर 10 अगस्त को मुख्यमंत्री द्वारा होमगार्ड जवानों को पुलिस कर्मियों के समकक्ष वेतन देने का आदेश जारी किया गया था। न्यायाधीश ने कहा कि जब से कोर्ट ने आदेश दिया है, उसी तारीख से होमगार्ड जवानों को पुलिस कर्मियों के समकक्ष वेतन का लाभ देना है। न्यायाधीश द्वारा झारखंड सरकार को चार सप्ताह के अंदर इसका पालन करने का आदेश दिया है।

टाटा के कोल सेक्टर कर्मियों का वेतन समझौता फाइनल

- न्यूनतम 12000 रुपये की हुई बढ़ोतरी, धनबाद, वेस्ट बोकारो आदि कर्मियों को मिलेगा लाभ

DHANBAD : टाटा स्टील, कोल डिवीजन के कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। उनका वेतन समझौता शुक्रवार को फाइनल कर लिया गया है। न्यूनतम 12000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। धनबाद, वेस्ट बोकारो सहित अन्य कोयला सेक्टर से जुड़े करीब 4200 कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। समझौते पर (इंटक) राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन के अध्यक्ष व विधायक जयमंगल सिंह, टाटा रीजनल कमेटी के सचिव संतोष महतो सहित प्रबंधन की ओर से वरीय अधिकारी मौजूद थे। जयमंगल सिंह ने कहा कि समझौते में कई और भी बातें हैं, जिसका श्रमिकों को लाभ मिलेगा।

बीएमएस ने कोल इंडिया, डीजीएमएस व सीएमपीएफ प्रबंधन के खिलाफ खोला मोर्चा, आंदोलन की घोषणा

यूनिट से मुख्यालय तक चरणबद्ध संघर्ष की बनी रणनीति, तैयार किया गया 17 सूत्री मांगपत्र

PHOTON NEWS DHANBAD: भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ ने कोल इंडिया, डीजीएमएस, सीएमपीएफ प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर तीन चरणों में आंदोलन की रणनीति तैयार की गई है। कोयला कामगारों से संबंधित 17 सूत्री मांग को लेकर आंदोलन किया जाएगा। महामंत्री सुधीर घुरडे ने बताया कि आंदोलन की सूचना व मांगों से संबंधित पत्र कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन, कोयला सचिव, डीजीएमएस, सीएमपीएफओ को सौंप दी गई है। सुधीर घुरडे ने शुक्रवार को कहा कि आंदोलन के पहले चरण में 1

से 10 सितंबर तक प्रत्येक इकाई स्तर पर श्रमिक जागरूकता के लिए द्वार सभा की जाएगी। द्वितीय चरण में 26 सितंबर को सभी क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। तृतीय चरण में 30 सितंबर को सभी कंपनी मुख्यालय के समक्ष धरना दिया जाएगा। इसके बाद भी प्रबंधन द्वारा समस्याओं के समाधान पर पहल नहीं हुई, तो आंदोलन तेज किया जाएगा।

इन मांगों के साथ होगा आंदोलन

- वेतन समझौता-11 में मंजूर मांगों का संपूर्ण क्रियान्वयन किया जाए।
- कोल उद्योग में कार्यरत मजदूरों को दुर्घटना होने पर सिंगरेनी कंपनी की तर्ज पर स्थायी मजदूरों को 1 करोड़ 15 लाख एवं ठेका मजदूरों को 40 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस लागू किया जाए।
- सभी अनुषंगी कंपनी में सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का निर्माण किया जाए एवं पर्याप्त पारा-मेडिकल स्टाफ की भर्ती कर कंपनी अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में दवा उपलब्ध की जाए।
- कैडर स्कीम में सुधार कर कंपनी में पुराने पद नाम जैसे (जनरल मजदूर, माइनिंग सरदार, ओवरमैन, डाटा इंट्री ऑपरेटर) इत्यादि में बदलाव किया जाए।
- कोल उद्योग में कार्यरत महिला सशक्तीकरण हेतु सभी अनुषंगी कंपनी में कमेटी का गठन किया जाए।
- सीएमपीएफ में ऑनलाइन प्रक्रिया शीघ्र अमल किया जाए।
- ईपीएफ की तर्ज पर कम से कम 15 हजार रुपये पर वित्त मंत्रालय द्वारा 1.16 का अंशदान पेंशन स्कीम में जमा किया जाए।
- न्यूनतम पेंशन एक हजार रुपये तुरंत एरियर समेत भुगतान किया जाए।
- भूमि अधिग्रहण के मुआवजा में बढ़ोतरी कर भू-आश्रित को पदस्थ करने में हो रही गड़बड़ी में सुधार किया जाए।
- सीपीआरएमएस स्कीम में कैशलेस इलाज सुनिश्चित किया जाए और स्मार्ट कार्ड सभी को यथाशीघ्र दिया जाए।
- रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट धारक माइनिंग संवर्ग के गैर अधिकारी से अधिकारी वर्ग में पदोन्नति हेतु पॉलिसी में आवश्यक सुधार किया जाए।
- सेवानिवृत कर्मचारियों का पेंशन रिवाइज किया जाए और बकाया एरिअर का भुगतान शीघ्र किया जाए।
- ठेका मजदूरों की समस्या जैसे 8 घंटा ड्यूटी बायो-मीट्रिक हाजिरी, वेतन, भत्ते, सुरक्षा, कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, बोनस, पीएलआर, एचपीसी वेज आदि का क्रियान्वयन किया जाए।

लोहरदगा में आदिवासी न्याय महा अभियान का जागरूकता रथ रवाना

LOHARDAGA : जनजातीय कार्य मंत्रालय के निर्देश पर 23 अगस्त से 10 सितंबर तक लोहरदगा जिले के चिह्नित 47 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह वाले गांवों में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान चलाया जाएगा।इसके लिए आज समाहरणालय परिसर से एक जागरुकता रथ को उप विकास आयुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।इस मौके पर उप विकास आयुक्त ने कहा कि इस जागरुकता रथ के जरिए आमजनों को इस अभियान की जानकारी दी जाएगी। जिले के 47 पीवीटीजी गांवों में लाभार्थी संतृप्त शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसमें आधार इनरोलमेंट व आधार कार्ड जारी करना, पीएम-जनधन के तहत बैंक खाते खोलना, सभी पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान भारत कार्ड नामांकन, सभी पीवीटीजी को सामुदायिक प्रमाण-पत्र जारी करना, सिकल सेल रोग और बुनियादी स्वास्थ्य मापदण्डों की जांच, वनाधिकार अधिनियम अंतर्गत मान्यता देना और उसके अनुसार वन पट्टा जारी करना के साथ-साथ छात्रवृत्ति योजना का लाभ देना, किसान क्रेडिट कार्ड, सामान्य निधि, एएससीडी मरीजों के लिए योजना आदि का लाभ दिये जाने का कार्य किया जाएगा।

कॉलेज कर्मियों को दो दिन में वेतन भुगतान करने का आदेश

DHANBAD: पीके राय मेमोरियल कॉलेज और एसएसएलएनटी महिला महाविद्यालय में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के मामले में श्रम अधीक्षक कार्यालय ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है। आउटसोर्सिंग कंपनी सामंता को दो दिन में कर्मचारियों का बकाया वेतन भुगतान का आदेश दिया है। ऐसा नहीं होने पर श्रम कार्यालय प्रिंसिपाल एम्प्लायर के खिलाफ कार्यवाई करेगी। इस आदेश से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों में खुशी है।

यह है मामला : बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय ने एक मई से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए सामंता नामक एक कंपनी को काम दिया है। यह कंपनी विश्वविद्यालय के साथ ही धनबाद और बोकारो जिले के कॉलेजों में भी कर्मचारियों की आपूर्ति करती है। मई का भुगतान तो कर्मचारियों को किया गया, लेकिन इसके बाद के दो माह का भुगतान नहीं किया। कर्मचारियों ने बार-बार कंपनी को वेतन भुगतान का आग्रह किया था, लेकिन वे नहीं माने।

इसके बाद इन कर्मचारियों ने श्रम विभाग का दरवाजा खटखटाया। इसी को लेकर श्रम अधीक्षक की ओर से मामले की सुनवाई की गई और फैसला दिया गया। कर्मचारियों ने झारखंड सरकार की ओर से निर्धारित न्यूनतम वेतन नहीं देने की भी शिकायत की थी।

एनआईए ने पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों के ठिकानों पर मारा छापा

CHAIBASA : राष्ट्रीय जांच एजेंसी, एनआईए ने गुरुवार को पश्चिमी सिंहभूम में भाकपा माओवादी नक्सलियों के सक्रिय सदस्यों के घरों पर छापेमारी की। जानकारी जांच एजेंसी द्वारा एक प्रेस नोट जारी करते हुए दी गई। चाईबासा में तीन स्थानों पर तलाशी ली गई। इसमें चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के पुसालोटा गांव, जेटेया थाना क्षेत्र बुरुरेंगरा और गुआ थाना क्षेत्र के लिपुंगा गांव स्थित संदिग्धों के घरों की तलाशी हुई। एनआईए की जांच के अनुसार यह संदिग्ध लोग प्रतिबंधित संगठन के वरिष्ठ नेतृत्व को नक्सली गतिविधियों को अंजाम देने में सहायता कर रहे थे। मामला जुलाई 2022 में आनंदपुर इलाके में सीपीआई (माओवादी) के शीर्ष नेताओं को संबोधित करते हुए लिखे गए आपत्तिजनक पत्रों की बरामदगी से जुड़ा हुआ है। नौ आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

बिरनी में तालाब से व्यक्ति का शव बरामद, हत्या की आशंका

शरीर में जख्म व गले में धारदार हथियार से वार के निशान

GIRIDIH : बिरनी के भलुवा कुम्हारबांध तालाब में शुक्रवार सुबह पानी में उपलाता एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ। शव को देखने के लिए आसपास के ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। घटना की सूचना भरकट्टा ओपी प्रभारी प्रकाश रंजन को मिलते ही पुलिस पदाधिकारी जितेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे। पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से बारिश के बीच तालाब से शव को बाहर निकाला। ग्रामीणों ने शव को देखते ही उसकी पहचान इसी थाना क्षेत्र के कल्याणपुर निवासी चतुरी महतो के 40 वर्षीय पुत्र पांचू यादव के रूप में की। पांचू यादव के घर के सामने करीब 300 मीटर दूर तालाब है।

घटना के बाद रोते-बिलखते परिजन ● फोटोन न्यूज

मुंबई से 19 सितंबर को धान रोपने आया था मृतक

मृतक की पत्नी मुंद्रिका देवी रो-रोकर कह रही थी कि उसके पति व पिता की किसी से दुश्मनी नहीं थी। दो साल बाद मुंबई से 19 जुलाई को धान रोपने आए थे। फिर मुंबई जाने के लिए नौ सितंबर को टिकट बनाकर रखा है। पति गुरुवार शाम को घर से जुटहाआम मोड़ की तरफ चौक पर प्रतिदिन की तरह निकला था। पति मोबाइल को घर पर ही छोड़ गए थे। रात्रि 9 बजे तक नहीं घर आए तो चौक पर जा कर खोजा गया। कहीं पता नही चला। सुबह जब बच्चे व अन्य लोग तालाब की तरफ शौच करने गए तो तालाब के पानी में पति का शव मिला। हल्ला होने के बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। वे घर के एकमात्र कमाऊ सदस्य थे। मृतक के वृद्ध माता-पिता रो-रोकर बेहोश हो रहे थे। चार पुत्र में मृतक सबसे छोटा पुत्र था।

प्रमंडल स्तरीय सहकारिता महासम्मेलन में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह हुईं शामिल

कोल्हान के 94 लाभुकों में बांटी गई 5 करोड़ की परिसंपत्ति

PHOTON NEWS JSR : साकची स्थित रवींद्र भवन के सभागार में शुक्रवार को प्रमंडलस्तरीय सहकारिता महासम्मेलन हुआ, जिसमें पूरे कोल्हान के 94 लाभुकों व समितियों के बीच 4 करोड़ 85 लाख रुपये से ज्यादा की परिसंपत्ति का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री (कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग) दीपिका पांडेय सिंह शामिल हुईं। इस अवसर पर मंत्री ने लाभुकों-समितियों के बीच परिसंपत्ति के रूप में सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग टूल किट, लाह खेती योजना अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले टूल किट्स, फसलोत्तर प्रबंधन योजना के तहत लैक स्क्रैपर सह क्रसर मशीन, केसीसी, माइक्रो एटीएम, मोबाइल वेंडिंग कार्ट, मत्स्य जीवी सहयोग समिति के लिए आईस बॉक्स, टाना जाल, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आदि वितरित किया गया।

मंच पर मौजूद मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ● फोटोन न्यूज

राज्य भर में बन रहे खाद्य गोदाम : मंत्री

अपने संबोधन में मंत्री ने कहा कि किसानों, सहकारी समिति के सशक्तीकरण के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए आगे आएं, सरकार पूरा सहयोग करेगी। सरकार का प्रयास है कि कृषकों के उत्पादों की खरीद-बिक्री, उपकरण संबधी सहयोग हो या कृषि ऋण माफी, धान अधिप्राप्ति में उचित समय में भुगतान हर दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं कृषि, पशुपालन के कार्यों का नेतृत्व करें। राज्य भर में 100 एमटी और 500 एमटी गोदाम बनाए जा रहे हैं, ताकि अनाज सुरक्षित रखा जा सके। 31 अगस्त तक सभी किसानों से उन्होंने फसल बीमा का लाभ लेने के लिए आवेदन करने की बात कही।

उन्नत उत्पाद से सशक्त बनाने का प्रयास : पोटका के विधायक संजीव सरदार ने कहा कि किसानों को सशक्त करने, कृषि के साथ-साथ अन्य व्यवसाय करने सहित कृषि, पशुपालन, बागवानी को बढ़ावा देने, नई तकनीक से उन्नत उत्पाद से आर्थिक समृद्धि लाने का प्रयास राज्य सरकार कर रही है।

गरीब कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकता : बहरागोड़ा के विधायक समीर मोहंती ने कहा कि राज्य सरकार समाज के हर तबके के उत्थान के लिए योजनायें चला रही है। कृषक-अन्नदाता की समस्याओं, उनके उत्पादों को सही कीमत दिलाने, कृषि के नई तकनीक से अवगत कराकर उनको आर्थिक रूप से समृद्ध करने का प्रयास सरकार कर रही है। महिला स्वावलंबन, कृषकों का आर्थित समृद्धि, गरीब कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

सहकारिता में पारदर्शिता आवश्यक : जुगसलाई के विधायक मंगल कालिंदी ने कहा कि किसानों के उम्मीदों-सपनों को साकार करने के लिए सहकारिता सशक्त माध्यम बन सकता है। उन्होंने सहकारिता के कार्यों को पारदर्शिता व ईमानदारी से लागू करने की आवश्यकता बताई ।

इनकी रही उपस्थिति : कार्यक्रम में निबंधक सहयोग समिति सूरज कुमार, उपविकास आयुक्त मनीष कुमार, पीडी-आईटीडीए दीपांकर चौधरी, तीनों जिला के सहकारिता पदाधिकारी, विभिन्न सहकारी संघों के प्रबंध निदेशक, लैम्पस-पैक्स, विशेष प्रकार के सहकारी समिति के अध्यक्ष, सचिव, कार्यकारिणी सदस्य कार्यक्रम में उपस्थित थे।

फोन पर लिंक भेज कर खाते से उड़ा लिए दो लाख रुपये

GODDA : जिले के पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव में एक महिला ने मोबाइल पर आए मैसेज के बाद बैंक खाते से दो लाख रुपये की ठगी का शिकार होने का मामला शुक्रवार को दर्ज कराया है। कंचन देवी, पति मनोज ठाकुर ने पोड़ैयाहाट थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। थाना प्रभारी विनय कुमार ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। कंचन देवी ने बताया कि 18 अगस्त को उनके मोबाइल पर एक एपीके का मैसेज आया।

उसने मैसेज को टच किया और इसके बाद रात 12 बजे से 4 बजे तक उनके बैंक खाते से दो लाख रुपये निकाल लिए गए। जब उन्हें यह पता चला, तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते इसी बीच एक लाख रुपये और निकाल लिए गए जिससे कुल मिलाकर दो लाख रुपये की ठगी हुई।

चतरा में एसबीआई के एटीएम से चार लाख की चोरी, रूम में लगाई आग

CHATRA : चतरा-हजारीबाग मुख्य पथ पर गुरुवार रात भारतीय स्टेट बैंक के तपेज शाखा के एटीएम को तोड़कर लगभग चार लाख रुपये की चोरी कर ली गई। एटीएम से चोरी के बाद एटीएम रूम में आग लगा दी। घटना की जानकारी लोगों को शुक्रवार को सुबह में तब हुई जब ग्राहक एटीएम से कैश निकालने के लिए पहुंचे। इसके बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। बैंक कर्मी आज कैश का मिलान कर रहे हैं। आग के कारण एटीएम जल गया और कमरे में जहां-तहां धुआ और कालिख का निशान जम गया है। जानकारी मिलने के बाद चतरा एसडीपीओ संदीप सुमन दलबल के साथ यहां पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। उन्होंने तपेज एसबीआई शाखा में लगे एटीएम के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की। हालांकि, इस घटना से संबंध में उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार किया। पुलिस भी घटना को लेकर विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि पूर्व में भी यहां लगे एटीएम को उखाड़ कर अज्ञात लोग ले गए थे। दो दिनों के बाद झाड़ियां से एटीएम को बरामद किया गया था।

रामगढ़ में एसबीआई का एटीएम काट कर ले गए लाखों रुपये

RAMGARH : शहर के गोला रोड बाजार टांड़ स्थित एसबीआई का एटीएम काटकर गुरुवार की रात चोरों ने लाखों रुपये उड़ा लिए। पुलिस के अनुसार, चोरों ने गैस कटर से एटीएम मशीन को काटा था। यह घटना एनएच किनारे और भीड़भाड़ वाले इलाके में हुई, लेकिन स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी शुक्रवार की सुबह मिली। सूचना पाकर रामगढ़ थाना प्रभारी सौरभ कुमार ठाकुर घटनास्थल पहुंचे। थाना प्रभारी ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है।

धर से शुरू करें बच्चों की नैतिक शिक्षा

कोलकाता में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर की जघन्य हत्या की गुत्थी उलझती जा रही है। पूरा देश हतप्रभ है कि यह हो क्या रहा है। जिस तरह की संभावना सीबीआई जांच में उभर कर आ रही है, वह सोच से परे की गिरावट का परिदृश्य पैदा करने वाली है। एक चिकित्सा संस्थान कैसे यौन अपराध का रैकेट चालक, ड्रग तस्करी में लिप्त और अवैध अंग तस्करी जैसी जघन्य गतिविधियों का ठिकाना हो सकता है। उस अपराध की शिकार महिला से बलात्कार के पीछे के कारणों में यदि अंग तस्करी और ड्रग तस्करी जैसी आपराधिक गतिविधियां भी जुड़ीं हों तो यह मामला अति गंभीर श्रेणी का हो जाता है, जिस पर से पर्दा उठना अत्यावश्यक हो जाता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि जिन के ऊपर न्यायिक प्रक्रिया में मददगार होने की प्रशासनिक जिम्मेदारी है, वही प्रशासन अपराधियों का संरक्षण करता दिखता है। स्वयं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का व्यवहार कितना ओछा और हैरान करने वाला है, जब वह प्रशासनिक कर्तव्यों का निर्वहन करने के बजाय स्वयं यात्रा निकाल कर घटना का विरोध करने निकल पड़ती हैं। यह समझ नहीं आता कि वह किसका विरोध कर रही हैं और किससे सजा दिलाने की मांग कर रही हैं। यह तो राज्य सरकार का ही कार्य है और वही राज्य की मुखिया हैं। शक के दायरे में कॉलेज के प्रिंसिपल का व्यवहार भी है। उसे बचाने के प्रयास क्यों किए जा रहे हैं। जिसे हत्या की सूचना पुलिस को समय पर न देने का जिम्मेदार ठहरा कर निलंबित किया जाना चाहिए था, उसे दूसरे कॉलेज का प्राचार्य बना कर पुरस्कृत करने या संरक्षित करने का कार्य हैरान करने वाला है। सवाल यह है कि हत्या के प्रकट मामले को आत्महत्या क्यों दिखाने के प्रयास हुए हैं। इसमें पुलिस प्रशासन की भूमिका क्यों संदिग्ध बनी हुई है। प्रथम दृष्टया हत्या दिखने वाले मामले को पुलिस आत्महत्या दिखाने का प्रयास करे तो यह बहुत गंभीर मामला बनता है। पूरे केस की जांच कर-के सच्चाई को न्यायालय के सामने अपराधी को दंडित करने के लिए पेश करना, असल जिम्मेदारी पुलिस की ही है। आरंभिक जांच में ऐसी कोताही बरतना अक्षम्य है। जांच के लिए घटनास्थल पर सबूतों को एकत्र करना, सबूतों को संरक्षित करना पुलिस की ही जिम्मेदारी है। इसमें पुलिस सोई हुई क्यों लगती है। क्यों घटनास्थल को खुला छोड़ कर साक्ष्यों को नष्ट करने का मौका अपराधिक तत्वों को दिया गया। जांच कार्य के बीच में ही घटनास्थल के साथ तोड़फोड़ करने के पीछे क्या मंशा है। ऐसे कई संदेह पैदा करने वाले तथ्य खबरों से निकल कर आ रहे हैं। वैसे ममता के कार्यकाल में अराजकता के अनेक मामले पहले भी उभरते रहे हैं। संदेशखाली की घटना तो अभी ताजा ही है। चुनाव के बाद की हिंसा में विरोधियों को प्रताड़ित करने की छूट और उस पर राजनेताओं और प्रशासन की चुप्पी, पंचायत चुनावों के बाद हुई खुली हिंसा पश्चिम बंगाल में प्रशासन की निष्पक्षता को संदिग्ध बनाती हैं, जहां विरोधी दलों के समर्थकों के साथ हिंसक प्रतिकार की छूट प्रशासन द्वारा दी जाती है। यहां तक कि गवर्नर और राज्य का उच्च न्यायालय भी इस पर टिप्पणियां करते रहे हैं। कानून व्यवस्था के मामलों में इस तरह का भेदभाव व्यवस्था को कमजोर करता है और आपराधिक भूमिका वाले लोगों के हौसले बढाता है। किसी भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था को इससे बचना चाहिए। प्रजातंत्र का मूल तो कानून का शासन है, जिसमें भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। शायद बंगाल वामपंथी शासन के समय की इलाका दखल संस्कृति से अभी उबर नहीं पाया है या ममता बनर्जी ने भी उसी कार्यप्रणाली को अपना लिया है, ताकि विरोध के स्वरों को उठने ही न दिया जाए। यह एकदलीय शासन की स्थापना की इच्छा का द्योतक है। विरोधी पक्ष भी ऐसी स्थितियों में राजनीतिक लाभ के चक्कर में पड़ने लग जाता है। एक ऐसी अस्वस्थ बहस होने लग जाती है कि आपके शासित राज्य में भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। सच में ऐसा हो भी रहा है। अभी देहरादून में एक मानसिक रूप से कमजोर लड़की के साथ दुराचार का मामला सामने आया है। अपराधी पकड़े गए हैं, किंतु मेरी गलती और तेरी गलती करके गलती माफ नहीं की जा सकती। असल बात यह है कि जहां भी ऐसी घटना हो, वहां अपनी प्रशासनिक और राजनीतिक जिम्मेदारी दलगत ओछी राजनीति से ऊपर उठ कर पूरी की जानी चाहिए। निर्भया मामले के बाद लगा था कि हालात सुधरेंगे, किंतु ऐसा नहीं हुआ। केवल कानून सख्त बना देने से काम होना वाला नहीं, कानून को लागू करने वाली मशीन भी गंभीर होनी चाहिए और अंत में यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हमारे बच्चों को नैतिक तरबियत, जो घर से ही दी जा सकती है, उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। कानून तो उल्लंघन करने वालों के लिए ही है। यदि आपराधिक सोच ही कम होती जाए तो ऐसी घटनाएं होना ही कम हो जाएंगी। यह काम तो घरों से ही शुरू होना चाहिए। आशा की जानी चाहिए कि पीड़ित महिला डॉक्टर को न्याय मिलेगा और आगे के लिए भी सुधार का मार्ग सुनिश्चित हो सकेगा। तब तक जागते रहें।

भारत के रक्षा उत्पादों का बढ़ रहा निर्यात

ANALYSIS

✍ प्रहलाद सबनानी

अब यदि देश की 60 प्रतिशत आबादी देश के सकल घरेलू उत्पाद में केवल 16-18 प्रतिशत तक का योगदान दे पा रही है तो स्वाभाविक रूप से इस क्षेत्र में गरीबी तो बनी ही रहेगी। परंतु, यह स्थिति अब धीरे धीरे बदल रही है क्योंकि हाल ही के वर्षों में भारत के विनिर्माण क्षेत्र का योगदान देश के सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते ग्रामीण इलाकों के नागरिक शहरी क्षेत्रों में स्थापित की जा रही विनिर्माण इकाईयों में रोजगार के नए अवसर प्राप्त करने के उद्देश्य से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। विनिर्माण क्षेत्र में कई ऐसे नए क्षेत्र भी उभरकर सामने आए हैं, जिन क्षेत्रों में भारत में उत्पादन बहुत कम मात्रा में होता रहा है। उदाहरण के लिए रक्षा क्षेत्र, दवा क्षेत्र, सेमी-कंडक्टर निर्माण क्षेत्र एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्षेत्र आदि का वर्णन यहां प्रमुख रूप से किया जा सकता है।

भारत में आज भी देश की लगभग 60 प्रतिशत आबादी ग्रामीण इलाकों में निवास कर रही है। वह अपने रोजगार के लिए सामान्यतः कृषि क्षेत्र पर निर्भर है तथा देश की कुल अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान केवल 16-18 प्रतिशत के आसपास बना रहता है। अब यदि देश की 60 प्रतिशत आबादी देश के सकल घरेलू उत्पाद में केवल 16-18 प्रतिशत तक का योगदान दे पा रही है तो स्वाभाविक रूप से इस क्षेत्र में गरीबी तो बनी ही रहेगी। परंतु, यह स्थिति अब धीरे धीरे बदल रही है, क्योंकि हाल के वर्षों में भारत के विनिर्माण क्षेत्र का योगदान देश के सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते ग्रामीण इलाकों के नागरिक शहरी क्षेत्रों में स्थापित की जा रही विनिर्माण इकाईयों में रोजगार के नए अवसर प्राप्त करने के उद्देश्य से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। विनिर्माण क्षेत्र में कई ऐसे नए क्षेत्र भी उभरकर सामने आए हैं, जिन क्षेत्रों में भारत में उत्पादन बहुत कम मात्रा में होता रहा है। उदाहरण के लिए रक्षा क्षेत्र, दवा क्षेत्र, सेमी-कंडक्टर निर्माण क्षेत्र एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्षेत्र आदि का वर्णन यहां प्रमुख रूप से किया जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में स्वदेशी रक्षा के क्षेत्र में उत्पादन की मात्रा 1.27 लाख करोड़ रुपये की रही है, जो पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय 16.7 प्रतिशत अधिक है। यह भारत सरकार द्वारा देश में उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकारी नीतियों और सरकार के प्रयासों की प्रभावशीलता को रेखांकित करता है। वर्तमान में रक्षा के क्षेत्र में उत्पादन करने वाली इकाईयों में सरकारी क्षेत्र की कंपनियों एवं निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा संयुक्त रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान उक्त

वर्णित उत्पादन में सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों का योगदान 79.2 प्रतिशत का रहा है, जबकि निजी क्षेत्र की कंपनियों का योगदान 20.8 प्रतिशत का रहा है। हर्ष का विषय तो यह भी है कि रक्षा के क्षेत्र में भारत में निर्मित किए जा रहे उत्पादों की अन्य देशों में भारी मांग निर्मित होती जा रही है और इन उत्पादों का निर्यात भी लगातार बढ़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 21,083 करोड़ रुपये के मूल्य का निर्यात भारत से विभिन्न देशों में किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 32.5 प्रतिशत अधिक है और यह भारत में रक्षा के क्षेत्र में हुए कुल उत्पादन का लगभग 20 प्रतिशत है। निर्यात में यह वृद्धि न केवल वैश्विक रक्षा बाजार में भारत के बढ़ते पदचिह्नों को दर्शाती है, बल्कि आत्मनिर्भरता और नवाचार के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। भारत में विनिर्माण इकाईयों की स्थापना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही के समय में कई रणनीतिक पहल भी केंद्र सरकार द्वारा की गई है। जैसे- मजबूत नीतिगत ढांचे को विकसित करना, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना, अनुसंधान एवं विकास कार्यों में पर्याप्त निवेश को बढ़ावा देना आदि। स्वदेशीकरण की नीति के अनुपालन का असर भी रक्षा के क्षेत्र में उत्पादन एवं निर्यात में हो रही भारी-भरकम वृद्धि के रूप में दिखाई देने लगा है। रक्षा के क्षेत्र में उपयोग होने वाले सैकड़ों उत्पादों के आयात पर रोक लगाकर इन उत्पादों का उत्पादन भारत में ही करने के निर्णय का असर भी अब धरातल पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। रक्षा के क्षेत्र में विभिन्न उत्पादों का उत्पादन भारत में ही करने की नीति को लागू करने से देश में न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि देश में आर्थिक प्रगति, तकनीकी उन्नति एवं रोजगार सृजन को भी बढ़ावा मिलेगा। रक्षा क्षेत्र की तरह ही हाल ही के समय में भारत ने उत्पादन के कई नए क्षेत्रों में प्रवेश किया है। कुछ वर्ष पूर्व तक दवा निर्माण के क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले एपीआई (एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट) नामक कच्चे माल का लगभग पूरे तौर पर चीन से आयात किया जाता था, परंतु कोरोना महामारी के दौरान भारत को यह अहसास हुआ कि यदि चीन इस कच्चे माल का निर्यात भारत को करना कम कर दे अथवा बंद कर दे, तो भारत में तो दवा उद्योग की इकाईयों में निर्माण कार्य ही ठप्प पड़ जाएगा। इसके बाद केंद्र सरकार ने एपीआई के उत्पादन को भारत में ही करने का फैसला लिया। आज स्थितियां पूर्णतः बदल गई हैं एवं एपीआई का निर्माण भारत में ही किया जाने लगा है। संभव है कि आगे आने वाले कुछ समय में एपीआई के निर्माण के क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भरता हासिल कर लेगा। भारत आज एपीआई के उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है एवं भारत की वैश्विक एपीआई उद्योग में 8 प्रतिशत की हिस्सेदारी बन गई है। आज भारत में 500 से अधिक प्रकार के विभिन्न एपीआई का उत्पादन किया जा रहा है। भारत में एपीआई का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय दवा उद्योग में तेज गति से वृद्धि दृष्टिगोचर हुई है और आज यह देश के सकल घरेलू उत्पाद में 1.72 प्रतिशत का योगदान देने लगा है। दवा उद्योग आज देश में रोजगार के करोड़ों अवसर निर्मित कर रहा है। भारतीय दवा उद्योग के वर्ष 2024 के अंत तक 6500 करोड़ अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2030 तक 13000 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। वर्ष 2013-14 के बाद से वर्ष 2021-22 तक भारतीय दवा निर्यात में 103 प्रतिशत की वृद्धि अंकित की गई है। जेनेरिक दवाओं के वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 20 प्रतिशत हो गई है, जिससे भारत को अब विश्व का फार्मेसी हब भी कहा जाने लगा है। केंद्र सरकार एपीआई के उत्पादन को भारत में बढ़ाने के उद्देश्य से एक समग्र एवं अनुकूल पारिस्थितिकीय तंत्र का निर्माण करने पर जोर दे रही है। वर्ष 2020 में केंद्र सरकार ने एपीआई के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के लिए 6940 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की थी। 35 सक्रिय दवा सामग्री का विनिर्माण, जो एपीआई का लगभग 67 प्रतिशत है, के लिए भारत के 90 प्रतिशत आयात पर निर्भरता है। वर्ष 2022 के बाद से भारत के फार्मास्यूटिकल व्यवसाय में जबरदस्त बदलाव आया है एवं भारत अब वॉल्यूम उत्पादक से एक मूल्यवान आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। दवा क्षेत्र में भारत अब वैश्विक स्तर पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को तैयार हो गया है। लगभग चार वर्ष पूर्व वैश्विक स्तर पर ऑटोमोबाइल विनिर्माण के क्षेत्र में सेमीकंडक्टर की उपलब्धतता में आई भारी कमी के चलते वाहनों के उत्पादन को भारी मात्रा में घटाना पड़ा था, परंतु इसके बाद केंद्र सरकार ने यह बीड़ा उठाया था कि सेमीकंडक्टर के निर्माण के क्षेत्र में भारत को वैश्विक हब बनाया जाएगा। भारत में सेमीकंडक्टर का बाजार 2,400 करोड़ अमेरिकी डॉलर का है, जो वर्ष 2025 तक बढ़कर 10,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर का हो जाने की सम्भावना है। इस संदर्भ में केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं एवं सेमीकंडक्टर की विनिर्माण इकाईयां भारत में अधिक से अधिक संख्या में स्थापित हों, इसके लिए भी केंद्र सरकार द्वारा गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। भारत द्वारा सेमीकंडक्टर उत्पादन में वैश्विक नेतृत्व हासिल किया जा सकता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वैश्विक स्तर पर कई प्रौद्योगिकी फर्म से भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग लगाने के लिए सीधे चर्चा भी कर चुके हैं। काउंटरप्वाइंट रिसर्च और इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत का सेमीकंडक्टर बाजार वर्ष 2026 तक लगभग 6,400 करोड़ अमेरिकी डॉलर का हो जाएगा। यह वर्ष 2019 के बाजार से तीन गुना अधिक होगा।

नौकरशाही में लेटरल एंट्री पर हो स्वस्थ बहस

केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में अहम पदों को संभालने के लिए संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने हाल ही में लेटरल एंट्री या कहें कि पार्श्व प्रवेश के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए एक विज्ञापन अखबारों में निकलवाया था। इसी को लेकर देशभर में गैर-जरूरी हंगामा खड़ा हो गया या निहित स्वार्थ से भरे लोगों द्वारा खड़ा कर दिया गया था। बहरहाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर केंद्र सरकार में लेटरल एंट्री पर रोक लगा दी गई है। यूपीएससी से कहा गया है कि वो लेटरल एंट्री से नियुक्ति न करे। कार्मिक विभाग के मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरमैन प्रीति सूदन को पत्र लिखकर कहा है कि इस नीति को लागू करने में सामाजिक न्याय और आरक्षण का ध्यान रखा जाना चाहिए। बात बस इतनी सी थी कि संघ लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञापन जारी कर कहा था कि केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में वरिष्ठ पदों पर काम करने के लिए प्रतिभाशाली भारतीय नागरिकों की तलाश है। इन पदों में 24 मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उपसचिव के पद शामिल हैं। कुल 45 पदों पर भर्ती होनी है। इस विज्ञापन के छपने के बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी सबसे ज्यादा हंगामा काट रहे थे। कह रहे थे कि केंद्र सरकार सरकारी विभागों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े लोगों को भर्ती करना चाहती है। हालांकि हमेशा की तरह राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए किसी तरह के प्रमाण देने की जरूरत तक महसूस नहीं की। श राहुल गांधी हवाई बातें-दावे करने में माहिर हैं। काश, राहुल गांधी को यह पता तो होगा ही कि देश के दस सालों तक प्रधानमंत्री रहे डॉ. मनमोहन सिंह को देश का वित्त सचिव तक लेटरल एंट्री के माध्यम से ही बनाया गया था। वह तब तक तो वह दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे थे। इसी तरह से मोंटेक सिंह अहलूवालिया को भी कांग्रेस सरकार ने ही योजना आयोग का चेयरमेन बना दिया था। उनकी नियुक्ति भी उसी तरह से हुई थी, जिस तरह से डॉ. मनमोहन सिंह की खुद की हुई थी। इसलिए यह कहना सरासर गलत है कि मौजूदा सरकार कुछ विभागों के लिए बाहरी अभ्यर्थियों को नौकरी देकर गलत कर रही है। ना जाने क्यों यूपीएससी के इस कदम ने नौकरशाही में लेटरल एंट्री पर बहस छेड़ दी। राहुल गांधी और कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे थे कि यूपीएससी की भर्ती की यह प्रक्रिया पीछे के दरवाजे से भर्ती है। इसे अंग्रेजी में बैक एंट्री भी कहा जा रहा है। अब कांग्रेस के नेताओं से यह तो पूछा ही जाना चाहिए कि सैम पित्रोदा और रघुरामन राजन कौन थे। उन्हें किस आधार पर सरकार में लेटरल एंट्री के तहत ऊंचे पदों पर नौकरी दी गई थी। अब जान लेते हैं कि लेटरल एंट्री होती क्या है। दरअसल नौकरशाही में लेटरल एंट्री का मतलब है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) जैसे पारंपरिक सरकारी सेवा कैडर के बाहर के व्यक्तियों को सरकारी विभागों में मध्यम और वरिष्ठ स्तर के पदों पर उनकी योग्यता और अनुभव के आधार पर भर्ती करना। इससे पहले लेटरल एंट्री के जरिए 2018 में पहली बार रिक्तियों की घोषणा की गई थी। लेटरल एंट्री करने वाले व्यक्तियों को आमतौर पर तीन से पांच साल के अनुबंध पर नियुक्त किया जाता है, जिसमें प्रदर्शन और सरकार की आवश्यकताओं के आधार पर विस्तार की संभावना होती है। इन व्यक्तियों से ऐसी विशेषज्ञता लाने की उम्मीद की जाती है, जो शासन और नीति कार्यान्वयन में जटिल चुनौतियों का समाधान करने में मदद कर सके। यूपीएससी के हालिया विज्ञापन से साफ था कि उसे तीन स्तरों पर योग्य उम्मीदवारों की तलाश थी- संयुक्त सचिव, निदेशक और उप शसचिव। इन पदों पर तैनात अफसर अक्सर विभागों के भीतर विशिष्ट विंगों के प्रशासनिक प्रमुख या उनके सहायक के रूप में कार्य करते हैं और प्रमुख निर्णय लेने वाले होते हैं। लेटरल एंट्री के पीछे सरकार का तर्क नई प्रतिभा लाना और प्रशासन में कुशल जनशक्ति की उपलब्धता बढ़ाना रहा। आप गौर करें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जब बोलते हैं, वे तब सरकार को सदैव कोसते ही रहते हैं। लोकतंत्र में सदा स्वस्थ्य वाद-विवाद और सार्थक संवाद जारी रहना चाहिए। हमेशा ही बेवजह विवाद नहीं खड़े करने चाहिए। खड़गे कह रहे हैं कि लेटरल एंट्री से सरकारी नौकरियों में हाशिये पर रहने वाले समुदायों को नुकसान होगा। राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को भी लेटरल एंट्री पर आपत्ति है। अब इन ज्ञानी नेताओं को कोई बताए कि लेटरल एंट्री का विचार तो सर्वप्रथम कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के दौरान ही विकसित किया गया था। लेटरल एंट्री पर महाभारत करने वालों को पता होना चाहिए कि यूपीएससी की भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी है। इसलिए इस मसले पर विवाद खड़ा करने का कोई ठोस आधार नहीं है। ऐसा करने वाले संवैधानिक संस्थानों पर आघात कर रहे हैं। दरअसल, यह तो कहना पड़ेगा कि देश में सियासत के संसार का माहौल बहुत विषाक्त हो चुका है। सरकार के हरेक कदम का विपक्ष मखौल उड़ाता रहता है या उसमें कमियां निकालने की कोशिश करता रहता है। अगर यही रणनीति विपक्ष अपनाता रहा तो सरकार अपना कोई काम कर ही नहीं सकेगी। यकीन मानिए कि विपक्ष से यह कोई नहीं कह रहा है कि वह सरकार को उसकी किसी जनविरोधी नीतियों पर न घेरे। अवश्य घेरे और उसकी जितनी चाहे निंदा करे, पर विपक्ष को सरकार के फैसलों की सोच-समझकर ही आलोचना करनी चाहिए। अगर उसने यह न किया तो उसकी जनता के बीच छवि तार-तार हो जाएगी और वह एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाने से वंचित हो जाएगा।

Social Media Corner

सच के हक में...

इसरो, भारत का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं गगन-यान मिशन की भी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही हूं जिसमें भारतीय अंतरिक्ष टीम को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। मुझे विश्वास है कि इन सभी मिशन के फलस्वरूप ऐसे परिणाम सामने आएंगे जिनसे देश सामाजिक, आर्थिक एवं वैज्ञानिक रूप से लाभान्वित होगा।

(राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का 'एक्स' पर पोस्ट)

नेपाल में हुई बस दुर्घटना की खबर से स्तब्ध हूं। तनहून जिले में मर्स्यांगदी नदी में गिरी 40 यात्रियों से भरी भारतीय बस के यात्रियों के लिए चिंतित हूं। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि दिवंगतों की शांति प्रदान करें। घायलों के समुचित इलाज एवं भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुझे पूरी उम्मीद है की केंद्र सरकार उचित कदम उठाएगी। अगर किसी झारखंडी को इस घटना से जुड़ी कोई मदद चाहिए तो वे तुरन्त हमारे हेल्पलाइन पर कॉल करें। हम आप तक पूरी मदद पहुँचायेंगे सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं।

(सीएम हेमंत सोरेन का 'एक्स' पर पोस्ट)

बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा जरूरी

लोकतंत्र जनता की, जनता द्वारा, जनता के लिए सरकार है, किंतु पांच अगस्त 2024 को जिस प्रकार से बांग्लादेश में बांग्लादेशियों द्वारा चुनी हुई शेख हसीना की सरकार का तख्तापलट हुआ, वो वैश्विक परिदृश्य में एक निंदनीय कृत्य है। बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री व राष्ट्रपिता की उपाधि से विभूषित बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान की प्रतिमा के साथ हुई बदसलूकी इन इस्लामिक जेहादियों की जाहिलियत और कट्टरता को दर्शाती है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा पूरे घटनाक्रम में अमेरिका और पाकिस्तान के षड्यंत्रों की आशंका के बावजूद भारत के तथाकथित स्वघोषित बुद्धिजीवियों अथवा आंदोलनजीवियों द्वारा इसे राजनीतिक अपरिपक्वता, छात्र आंदोलन, तानाशाही व निरंकुश शासन का परिणाम बताना आम भारतीयों के लिए चौंका देने वाला है। बांग्लादेशी सरकार के तख्तापलट से पहले और बाद में होने वाली घटनाओं का बारीकी से अध्ययन करने पर पता चलता है कि इनका पैटर्न 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग और मुहम्मद अली जिन्ना द्वारा कारित ' डायरेक्ट एक्शन ' से मिलता जुलता है, जिसका एकमात्र उद्देश्य हिंदुओं का नरसंहार, हिंदू महिलाओं का बलात्कार, अपहरण, हिंदुओं की संपत्ति का अपहरण, लूटपाट व जाति विशेष का समूल नाश है। इस बीच भारत के बंटवारे से पहले 1941 में मौलाना अबूल आला मौदूदी द्वारा लाहौर में स्थापित जमात-ए-इस्लामिक जो कि एक इस्लामिक राजनीतिक दल है, जिसका मकसद खुदा की सल्तनत स्थापित करना है और जिसकी एक शाखा जमात-ए-इस्लामिक (जेईएल) बांग्लादेश में भी सक्रिय है, की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। पहले जेईएल बांग्लादेश अथवा जेल बांग्लादेश ने अवामी लीग की सरकार से करीबियों का फायदा उठाकर अपने जेहादी कट्टरपंथियों को ऊंचे पदों पर बैठाकर भविष्य में होने वाली हिंसा की तैयारियों को सुनिश्चित किया, जिसमें हिंदू आबादी वाले क्षेत्रों में जेहादियों की भर्ती, हिंदुओं के मंदिरों व प्रतिष्ठानों की मार्किंग की गई जिससे दंगों के दौरान उग्र भीड़ की आड़ में हिंदू नरसंहार व महिलाओं के बलात्कार को वीभत्स तरीके से अंजाम दिया जा सके। जेल बांग्लादेश ने छात्र आंदोलन को देशव्यापी बनाकर अवसर मिलते ही शेख हसीना को देश से निष्काषित कर अपने मंसूबों को अंजाम दिया और बर्बरतापूर्ण वीभत्स तरीके से खुलेआम नरसंहार और बलात्कार की घटनाओं को अंजाम दिया, जिसमें अबतक लगभग दस हजार लोगों के हताहत होने का अनुमान है। ढाका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अब्दुल बरकत की 2016 में प्रकाशित पुस्तक के अनुसार 1964 से 2013 के मध्य बांग्लादेश में लगभग एक करोड़ हिंदू आबादी हत्या, अपहरण, धर्म परिवर्तन अथवा विस्थापन के कारण विलुप्त हो गई। ध्यान देने योग्य तथ्य है कि 1950 में बांग्लादेश में हिंदू आबादी 22 प्रतिशत थी, जो आज घटकर लगभग आठ प्रतिशत बची हुई है। वर्तमान में बंगलादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का ढाकेश्वरी मंदिर जाना अथवा हिंदू अल्पसंख्यकों के संरक्षण व संवर्धन की बातें करना 1950 के नेहरू-लियाकत समझौते की तरह कोरी कल्पना लगती है, जिसका पालन भारत ने तो किया किंतु पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक आज भी अपने अधिकारों व संरक्षण की बाट जोह रहे हैं। आज जरूरत है कि हम ' वसुधैव कुटुम्बकं ' और ' सर्वे भवंतु सुखिनः ' के साथ-साथ भारत की सरकार व हिंदू समाज ' वीर भोग्या वसुंधराः ' के मंत्र की अनुपालना में इजरायल की सरकार व यहूदियों से सीख लेते हुए बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए सभी मोर्चों पर मजबूती से अपनी भावाभिव्यक्ति को रखें, क्योंकि कट्टरपंथी जेहादियों के दमन का मात्र यही एक रास्ता शेष है, जिसे धर्मनिरपेक्षता के दृष्टिकोण से देखना असंभव है।

बिहार में भूमि सर्वेक्षण कार्य

बिहार में शुरू हुआ भूमि सर्वेक्षण कार्य प्रशंसनीय और स्वागतयोग्य है। देश के ज्यादातर राज्यों में भूमि सुधार का कार्य पूरा हो चुका है, पर बिहार में दशकों से इसका इंतजार रहा है। वैसे राज्य के 20 जिलों के 89 अंचलों में सर्वेक्षण पहले से चल रहा था, जो अब लगभग पूरा होने को है और बचे हुए 445 अंचलों में सर्वे अब शुरू हुआ है। गौर करने की बात है कि अमीन, कानूनगो और सहायक बंदोबस्त पदाधिकारियों की कमी की वजह से इन अंचलों में सर्वेक्षण का काम रुका हुआ था। इन पदों पर संविदाकर्मियों की बहाली हुई है, जिन्हें प्रशिक्षण के बाद भूमि सर्वेक्षण कार्य में तैनात कर दिया गया है। वैसे तो बिहार में काफी हद तक भूमि विवरण का डिजिटलीकरण हो चुका है और काफी कुछ ऑनलाइन उपलब्ध है, मगर जब संपूर्ण भूमि सर्वे संपन्न हो जाएगा, तब एक-एक भूखंड के बारे में जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगी। जमाबंदियों में सुधार की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साल 2025 में राज्य विधानसभा चुनाव से पहले ही सर्वे को पूरा करने पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने आदेश के साथ ही अधिकारियों से एक तरह से हाथ जोड़कर आग्रह भी किया है कि भूमि सर्वेक्षण में तेजी लाई जाए। वास्तव में, बिहार में भूमि सर्वेक्षण के काम को कभी गंभीरता से नहीं लिया गया। भूमि संबंधी रिकॉर्ड लोगों के भरोसे ही चल रहे हैं। गांवों में जाकर रिकॉर्ड सुधारने का काम पहले ही हो जाना चाहिए था, पर इच्छाशक्ति की कमी के साथ ही, कर्मचारियों की कमी भी एक बड़ा बहाना बनती आ रही थी। सर्वे को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए अब करीब 9,888 लोगों को नियुक्ति दी गई है। हालांकि, सावधान रहना होगा कि सर्वे का काम अनुभवी लोगों के नेतृत्व में ही संपन्न हो। बडे. अधिकारियों के साथ ही छोटे कर्मचारियों को भी पूरी ईमानदारी से इस काम को अंजाम देना चाहिए।

Printed and Published by Fahim Akhtar on behalf of MAA MEDIA VENTURE and Printed at SHIVA SAI PUBLICATION PVT.LTD, Ratu, Kathitand, Near Tender Bagicha, H.P. Petrol Pump P.O.+P.S.- Ratu, Dist.-Ranchi, 835222, Jharkhand And Published at Roshpa Tower, 5th Floor, Main Road, Ranchi, Jharkhand-834001. R.N.I Number - JHABIL/2022/85899, Editor- Fahim Akhtar. Mob - 9431311669, E-mail : thephotonnewsjharkhand@gmail.com

Unease of doing research in India

THE Indian Institute of Technology-Delhi (IITD) and a few other top-ranking research and academic institutions have received notices for payment of Goods and Services Tax (GST) for research funding they received in the past five years. The amount for IITD, with interest and penalties, is said to be Rs 120 crore. While the academic and scientific community has not reacted to the issue openly, entrepreneur and investor TV Mohandas Pai has called it "tax terrorism at its worst". Just a month ago, Finance Minister Nirmala Sitharaman increased the customs duty on lab chemicals from 10 per cent to 150 per cent in the Budget. Enzymes, reagents and chemicals of high purity are crucial for research and they are usually imported. The bizarre move sent the scientific community into a tizzy as this overnight increased the cost of ongoing and future projects. The steep hike was rolled back in response to an outcry by scientists in the media and on social media platforms.These are not isolated incidents that one could brush aside as bureaucratic oversight, but seem to be part of a process to undermine public-funded research and higher education. The tax notice on research funding comes a couple of years after the increase in GST rates on technical tools from 5 per cent to 18 per cent. This made the procurement of scientific and technical instruments, equipment, accessories and consumables very costly. Worried at the likely impact on scientific research, the office of the Principal Scientific Adviser (PSA) sent a note to the government mentioning that "while the private organisations may gradually absorb the impact of rate changes, there is a limited space for public-funded organisations to absorb the impact". The Ministry of Finance tried to pacify the PSA, promising additional allocation of funds to cover the actual impact of the GST hike. Still, the government has done little to ease the situation, as is clear from the recent GST notices and the (now withdrawn) customs duty hike on lab chemicals.

Research and innovation can flourish in an environment where the government adequately funds research, encourages collaboration and creates a suitable ecosystem (regulation, taxation, etc.) to boost research and development. On all these counts, India is doing badly.

India's funding for R&D is very low — below 1 per cent of the GDP. The much-touted umbrella research funding agency, Anusandhan National Research Foundation (ANRF), has been in the making for the past five years. The government has repeatedly claimed that it has substantially increased the funding available for R&D, citing in successive Budget speeches an 'outlay' of Rs 50,000 crore over five years for the new agency. The 'outlay' is a misnomer. It has been clarified that government funding will only be 30 per cent of this and the rest 70 per cent will be raised from the private sector. If this is so, the state funding will come to a minuscule Rs 3,000 crore a year — which is substantially lower than the current budget of science-related departments. The Ministry of Science and Technology has been allocated Rs 16,628 crore for 2024-25. The ANRF is a clear move to shift the burden of R&D to the private sector, but there is no pathway visible for doing so.Along with the fund crunch, researchers face red tape in terms of accessing funds, dealing with tax requirements, delays in disbursal of scholarships and fellowships and meeting mandatory conditions like procuring equipment that fulfils 'Make in India' requirements. "How will you focus on research if you have to do firefighting all the time?" commented a scientist from IIT-Kanpur on social media platform X. There are other issues that stifle research, such as restrictions on international travel grants and conferences at a time when research in critical areas is becoming increasingly collaborative.Last year, the Foundation for Advancing Science and Technology (FAST) surveyed researchers of 10 top-ranking institutions to gauge the level of 'Ease of Doing Science' (EoDS) — a phrase coined by Prime Minister Narendra Modi in 2015. Only 6 per cent of the respondents rated any parameter as 'very good' for EoDS.

Don't lower the bar in pursuit of excellence

Affirmative policies should be aimed at enabling the disadvantaged to achieve highest standards possible

ONE of the most difficult challenges for any society, but especially a developing society, is achieving the right balance between the pursuit of excellence and the demand for equity and inclusion. The pursuit of excellence demands high standards and merit-based selection. A policy of inclusivity leads to affirmative action to elevate the opportunities for disadvantaged sections of society. Ideally, such affirmative policies should be aimed at enabling the disadvantaged to achieve the highest standards possible through preferential education, skilling and training support. This may be more challenging but in the longer run more rewarding both for society and the individuals concerned. This would also engender intangible gains in enabling these individuals and the communities they come from to enjoy enhanced respect and self-esteem.The politically easier route to follow is to aim at greater inclusivity through lowering of entry standards in a wide range of professional institutions and activities, including those engaged in imparting education and capacity-building. This invariably sets in motion a cumulative downward dynamic of falling standards and lowered entry requirements at each successive stage. Since a modern economy with advancing technological imperatives cannot do without a highly qualified workforce, one ends up with establishing islands of excellence either exempt from the observance of affirmative policies or which have token representation of disadvantaged communities.

Creating and running such islands of excellence may deliver good results in the short term, but they tend to remain islands, minus an ecosystem of high-quality education, training and skill acquisition. India's highly acclaimed space and nuclear programmes are zones of excellence in a sea of mediocrity. This may also be the fate of the currently celebrated Global Capability Centres mushrooming in India.In India, affirmative policies are rightly the responsibility of the state. The private sector has so far been able to avoid having to follow similar policies. In the public sector, we have already witnessed the downward dynamic referred to earlier. When I joined the Indian Foreign Service (IFS) in 1970, the age requirement for entry was the 21-24 bracket, with two chances for appearing in the civil service examinations. The personal interview was given much greater weightage — 400 marks in the case of the IFS and 300 for the IAS. Even if a candidate passed with high marks in the written exams, a below-the-passing-grade in the interview for the IFS meant disqualification. For the reserved categories, the marking was separate from the general category. They did not compete with the latter. Currently, the age bracket in the general category is 21-32, with six attempts allowed within this limit. For the OBC category, the age limit goes up to 35 and with nine attempts allowed. For Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the upper age limit has been raised to 37, with unlimited attempts permitted.

The personal interview has lost its relevance since even a zero grade would not disqualify a candidate as long as he has sufficiently high grades in the written exams. There are no studies or data to show whether the progressive lowering of entry conditions both for the general and reserved categories has served the objective of greater inclusion and social equity. Anecdotal evidence points to mounting economic and social inequalities and persistent caste and gender discrimination. There has been a steady decline in the quality of state capacity and governance. A civil servant joining any of the All-India or Central Services at the age of 32 is unlikely to be moulded into the culture and ethos of the civil services. The wide age disparities among the entrants does not encourage the kind of bonding that the younger entrants developed while training together. What would a 21-year-old have in common with a 37-year-old colleague?In the state civil service, the situation is worse. The age bracket is from 21 to the ripe old age of 40!The government and the public sector play the most critical role in managing a country of the complexity of India, facing challenges that demand exceptional skills and abilities. The current policies are neither delivering social justice nor good governance. That is short-changing the country and its people.Human resource is the most important resource a country has. This is not a cliché. It is the only resource which grows as it is expended. During the turbulent Cultural Revolution (1966-76) in China, Mao encouraged the denigration of intellectuals, scientists and experts. It was "better to be Red than an Expert". Educational institutions were closed and intellectuals and professionals and students were all sent down to the countryside to learn from the masses. An entire generation was lost to the country. One of the first reforms that Chinese leader Deng Xiaoping introduced when he assumed power in 1976 was to reopen educational institutions, rehabilitate intellectuals and professionals and begin sending thousands of Chinese youth, year after year, to the best universities in the West. China's own educational institutions eagerly sought the services of top foreign academics and teachers to educate the incoming generation of the Chinese. Several Indian-American scientists and academics were also invited to spend part of the academic year in China, paid generous compensation and enabled to carry out teaching and research in the manner they were accustomed to do in the US. In India, they are not particularly welcome. Thanks to the pragmatic policies it adopted, China today has a pool of talent and scholarship that is second only to the US. India has fallen behind.

So, what needs to be done? First, it is not enough to set up more universities, institutes of technology and centres of excellence. Greater effort is needed to provide universal high-quality primary and secondary education which will then feed into tertiary institutions.Second, children entering the education stream need to have good nutrition and healthcare so that they are not stunted both physically and mentally. Without this strong base, the top-heavy structures we create will topple over eventually.And three, the state sector must strive to be the most capable, dispensing high-quality governance through the best and the brightest the country has to offer.

32 years later

The enduring trauma of rape victims

THE 1992 Ajmer rape case, in which around 100 schoolgirls were sexually assaulted and blackmailed, points to the deplorable state of justice in India. The sentencing to life of four accused on Tuesday, 32 years after the heinous crime, underscores the systemic failures that allow such atrocities to persist. Despite the existence of stringent laws meant to protect women and deter sexual crimes, the grim reality is that justice remains elusive for many victims.This case was part of a horrifying racket that preyed on young school- and college-going girls in Ajmer. They were blackmailed and sexually exploited by men wielding significant influence, political and financial. Among the most notorious of these predators were Farooq Chishti and Nafis Chishti, Youth Congress leaders who brazenly used their power to silence the girls. Their ability to manipulate the system led to attempts to erase evidence of their crimes, complicating the pursuit of justice. Traumatised, some victims even died by suicide.

Much like the recent Kolkata incident where a doctor was brutally raped and murdered, echoing the infamous Nirbhaya case, the Ajmer case is another symbol of the pervasive culture of violence against women. The delay in delivering justice in these cases not only exacerbates the trauma for the victims but also erodes public trust in the legal system as perpetrators manage to evade culpability for years, if not decades. The real change will come when these laws are enforced promptly, when the culprits are held accountable without delay and when the victims' voices are heard and respected. The pursuit of justice must not be an afterthought, but a priority, to ensure that such tragedies are curbed, even as our society is today rattled by protests over the doctor's rape-murder and the sexual abuse of two kindergarten girls in Badlapur, Maharashtra.

Constitutional morality is getting short shrift

Constitutional morality is not only for our constitutional authorities and other leaders; it must pervade the entire community.

DO our constitutional authorities believe in constitutional morality? Some perhaps don't. Time and again, we learn of some unexpected and strange development at the instance of a constitutional authority. The trouble is that such developments are not confined to one or two constitutional authorities, but are more or less across the board and frequent. The question is: who will advise them? They damage the constitutional spirit and virtually mock at our Constitution framers and the faith they had in the character and integrity of our leaders of the future.

It could truly be said that in the past as well, our leaders abused the Constitution, but that cannot be reason or justification for the present-day abuse. The attempt should be to avoid a downward spiral rather than create a whirlpool. Constitutional morality requires the authorities to do the right thing rather than avoid it; it requires the authorities to adhere to the rule of law rather than circumvent it; it requires maintenance of high ethical standards rather than looking for the lowest common multiple. Let's consider a few examples.

In Maharashtra, the state government advised the Governor to nominate members to the Legislative Council. The Governor took no action on the recommendations for as long as eight months — he neither rejected nor accepted them. He simply shelved the advice. This led to a public interest litigation in the Bombay High Court. While deciding the case, the high court made a public law declaration that the Constitution obliges the Governor to either accept or return the recommendations within a reasonable time and eight months is beyond reasonable. It was further held that to subserve the aims set by the Constitution, it would be eminently desirable if the obligation is duly discharged without undue delay. Guess what? The Governor still took no action. Was it the right thing to do? Subsequently, the government fell and the new government made different recommendations which were promptly accepted by the Governor. Constitutional morality had been thrown out of the window.There are many such instances from the recent past and some are playing out even as you read this. Some of our Governors have delayed assent to Bills passed by the state legislature; others have unreasonably withheld assent for months and years, compelling at least two state governments to approach the Supreme Court to interpret the power of the Governor in such matters.

The Speaker of the Legislative Assembly in Manipur, also a constitutional authority, gave no importance to constitutional morality. He did not take any action for more than three years on alleged violations of the anti-defection law contained in the Tenth Schedule of the Constitution. One of the persons against whom the allegations were made was a minister in the Cabinet. The Speaker is expected to be non-partisan, but he took no decision, thereby favouring the minister. Could the Speaker indefinitely delay taking a decision? The Supreme Court answered it in the negative and required the Speaker to take a decision within a month, which the court thought was reasonable, considering the passage of time. The Speaker did not do so and asked for an extension of time; he later assured the court that a decision would be taken by a certain date. No decision was taken. Was it the right thing to do, especially after an assurance given to the apex court? In view of the extraordinary circumstances presented, the court was compelled to pass a direction preventing the minister concerned from entering the Legislative Assembly. That's when matters came to a head. By the way, this Speaker is not alone in such a misadventure.The Chief Minister of a certain state is also guilty of disregarding constitutional morality. In West Bengal, a minister continued to hold office despite having been arrested and put in jail. The CM did not sack him for three months. In Tamil Nadu, the CM did not sack a minister who was in jail for eight months. The minister eventually resigned a day before the issue was raised in the Madras High Court. In Delhi, the CM sacked a minister only after he had spent nine months in jail. Ironically, now the CM himself is in jail and has not resigned, unlike his counterpart in Jharkhand. These are some instances where constitutional morality has been disregarded. Is it good for our country? BR Ambedkar understood constitutional morality as "a paramount reverence for the forms of the Constitution". Understandably so. The Constitution is not and cannot be in the nature of a standard operating procedure. If the forms of the Constitution are not treated as sacred, all will be lost. Perhaps that is why Rajendra Prasad said that our country needed leaders of character and integrity.

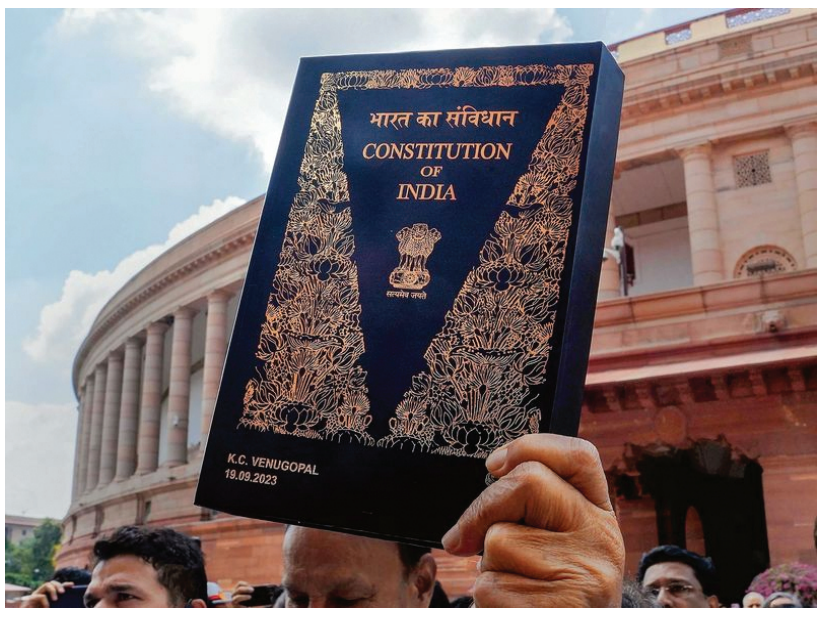

Constitutional morality is not only for our constitutional authorities and other leaders; it must pervade the entire community. Otherwise, an obstinate minority may stymie the working of an institution, even though it may not be strong enough to gain ascendancy. This can happen in any institution. As far as Parliament or state legislatures are concerned, constitutional morality does not permit a complete disruption of proceedings by a vocal minority. Such a disruption cannot be and should not be sanctified as legitimate parliamentary strategy, as canvassed by a former minister. It goes against the grain of constitutional morality. Similarly, calls for love jihad, land jihad and flood jihad are all constitutionally unacceptable transgressions. Garlanding rapists and murderers cannot be the right thing to do. We are passing through somewhat troubling and difficult times. We must respect our Constitution and its spirit and ethos as well as the rule of law. If we don't, we will be creating that whirlpool that will take us to the depths of the Indian Ocean.

Hindalco to invest USD 10 billion in Indian ops, Novelis

NEW DELHI. Kumar Mangalam Birla, chairperson of Aditya Birla Group, said Hindalco Industries' expansion across the India business and US-based subsidiary Novelis will entail investments of $10 billion for ongoing projects as well as the ones envisioned in the near- -term. This includes the Aluminium and Copper smelter expansions, Aditya FRP plant, the new alumina refinery in Rayagada, and the Bay Minnette expansion in Novelis.

During the annual general meeting on Thursday, Birla said Hindalco is setting up a greenfield alumina refinery in Rayagada, Odisha. The first phase of 850,000 tonne is expected to be commissioned in FY27. Hindalco is evaluating a nearly 200,000 tonne-brownfield expansion at its Aditya Aluminium smelter in Odisha, which will be substantially powered by renewable energy.It has plans to expand its copper smelting capacity and is exploring setting up a brownfield facility in Gujarat.

"Our company is building India's largest Copper Inner Groove Tube plant at Wagodia, Gujarat. This project will be commissioned by the end of this calendar year and will reduce import dependence for this key component in air conditioners," said Birla.

Birla stated there are macro factors driving consumption of aluminium and copper. He said aluminium consumption – which was at 5 million tonne (MT) in FY24 — will double to 10 MT over next decade. He expects copper consumption to grow 10% over next few years."Hindalco is using this opportunity to expand capacities and add new products and solutions that cater to India's emerging needs such as infra for EVs and solar energy," said Birla. On Novelis, he said it continues to make steady progress across a number of strategic capital investments. The largest among these is the US rolling and recycling investment in Bay Minette.

Macro factors driving aluminium, copper consumption

Birla stated there are macro factors driving consumption of aluminium and copper. He said aluminium consumption – which was at 5 million tonne (MT) in FY24 — will double to 10 MT over next decade. He expects copper consumption to grow 10% over next few years.

Scooter portfolio to do better than industry growth: TVS

NEW DELHI. Two-wheeler major - TVS Motor Company - is confident that its scooter portfolio will continue to better industry growth rate. The automaker also expects a very healthy festive season this year.

"When the two-wheeler industry was growing at 4% CAGR, scooter sales were growing at 8%. Our scooter portfolio has grown by 12% and Jupiter, as a brand, alone has grown by 24%. I want to take this growth much ahead of the industry…I want to better 12% when the industry is growing at 8%," said KN Radhakrishnan, Director & CEO at TVS Motor Company.The CEO also anticipates the share of scooters in total 2-wheeler sales to go as high as 40% in the coming years due to the product's practicality. At present, scooters account for 32% of 2-wheeler sales and including electric vehicles, it goes up to 36%.The CEO's statement comes as the Chennai-based company on Thursday launched the all-new TVS Jupiter 110 at a starting price of `73,700 (ex-showroom, Delhi). Developed with an investment of `150 crore, TVS Motor has high hopes from the updated version of its most popular scooter brand."This product will delight every customer in India, whether it is rural, urban or semi-urban… Jupiter 110 and Jupiter 125 have also got a huge opportunity in the international market," said Radhakrishnan. In the international market, TVS sees big opportunities to expand in the ASEAN region.

He projected double-digit growth in two-wheeler industry volumes during this year's festival season on the back of robust rural market demand."Currently, the momentum is very good and this year - the Diwali and Puja season - is going to be great. Currently, we are growing around 12.5% kind of growth, as per the VAHAN data...I am optimistic that this season is going to be much better than 12.5% growth," said Radhakrishnan.

Festival season, an important period for the automobile industry, is set to kick in with Onam in Kerala in the first half of September and would last till Bhai Dooj after Diwali in November.

GST rate rationalisation: GoM not keen on tweaking current slabs for now, seeks more data

New Delhi. The reconstituted Group of Ministers (GoM) on rate rationalisation under the Goods and Services Tax (GST) regime met for the first time on Thursday and broadly agreed to not make any changes with the existing slabs in the indirect tax regime. State finance ministers, who participated in the meeting, also said that the issue of reduction of GST rate in health and life insurance premiums was raised in the meeting of the GoM and it is being reviewed by the fitment committee.

GoM members have sought more data on various items after which it will make a detailed presentation on rate rationalisation proposals at the GST Council meeting slated for September 9. The GoM will then meet again in September-end, state finance ministers said. Bihar's Deputy Chief Minister Samrat Chaudhary, who is the convenor of the GoM on rate rationalisation said some members of the GoM were not in favour of any tweaks in the existing tax slabs under GST. "All matters were discussed. We will have further discussions. For now, every member has given their views. Some are demanding that there should be no changes in tax slabs under GST. More discussions will happen and then only a final decision will be taken," he said.

On reducing GST on insurance, Chaudhary said there have been deliberations on it but no decision has been taken. Chaudhary said he has received representations from some associations such as beverages, online gaming, and they will review those and some will be sent to the fitment committee.Other members of the GoM also supported the view of no change in GST slabs as of now. West Bengal's Finance Minister Chandrima Bhattacharya said she was of the view that there should be no changes in the GST slabs.

Explained: Why Reliance shares gained ahead of upcoming AGM

New Delhi. Shares of Reliance Industries rose 1% to Rs 3,022.65 in early trade on Friday, pushing its market capitalization near the Rs 20.5 lakh crore mark.The shares of the company rose as a result of increasing optimism from both domestic and global brokerage firms ahead of the company's Annual General Meeting (AGM) on August 29.Analysts are forecasting significant announcements related to the possible demerger or separate listings of the company's telecom and retail divisions.Bernstein remains bullish on Reliance Industries, driven largely by Reliance Jio's growth momentum. The brokerage has raised its target price for RIL, citing higher valuations due to recent tariff hikes by the telecom arm that outpaced previous expectations and the completion of its 5G rollout.The brokerage projected a 16% compound annual growth rate (CAGR) in revenue and a 20% CAGR in earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA) for Jio over the next three years. It expects the benefits of the recent tariff hikes to be reflected in FY2025.Bernstein also noted that Reliance's retail operations have focused on operational efficiency by moderating capital expenditure and rationalizing store operations. Meanwhile, oil-to-chemicals (O2C) earnings have remained stable.The brokerage has now revised its target price for Reliance Industries from Rs 3,190 to Rs 3,440.It may be noted that RIL's stock has gained around 17% in 2024 so far, and the next phase of growth is expected to come from 5G monetisation and the scaling up of broadband services.CLSA has also maintained its 'Outperform' recommendation for Reliance Industries with a price target of Rs 3,300 per share.

Other market observers are watching for updates during the AGM on the company's new energy business, its debt status, and its capital expenditure plans.

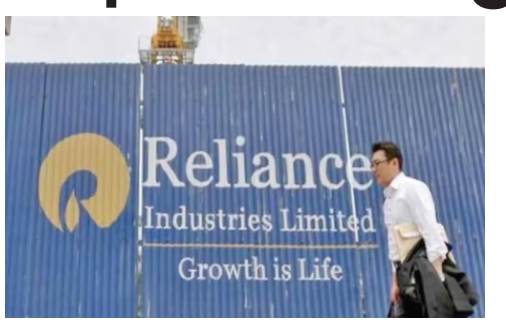

The demerger of retail and/or telecom is another focal point for investors.

Reliance report card

According to Reliance's FY24 annual report, the company is poised to tap into financial markets when needed to raise capital for its growth plans.In particular, the company highlighted the progress in its new energy business, announcing advancements in setting up five giga factories as part of its ambition to achieve net carbon zero by 2035.In the O2C segment, challenges persist with weaker petrochemical margins due to new capacity additions and muted demand. However, refining margins remain robust, driven by steady global oil demand.Reliance's digital business has also been a highlight, with the company underscoring the advantages of its 5G rollout via standalone architecture, which sets it apart from competitors.Jio's pan-India launch of JioAirFiber has significantly expanded its market, helping it to target 10 crore users. Additionally, the company continues to push its JioBharat phone initiative, aimed at making India '2G-free'.

The digital business' capital expenditure stood at Rs 57,400 crore for FY24, pushing total investments in the segment to $86 billion. The company reiterated its focus on expanding consumer brands and strengthening its Digital/New Commerce capabilities.

Rupee rises 5 paise to 83.88 against US dollar in early trade

Paytm has proposed reduced remuneration for board members, as part of efforts towards responsible financial discipline and corporate governance

Mumbai. Rupee traded in a narrow range and appreciated 5 paise to 83.88 against the US dollar in morning trade on Friday, supported by easing crude oil prices and fresh foreign fund inflows.

Forex traders said significant correction in oil prices, which is hovering around USD 77 per barrel, is a major positive for the rupee, given India's substantial oil imports.At the interbank foreign exchange market, the local unit opened at 83.93 and then gained ground and touched 83.88, registering a rise of 5 paise from its previous close.

On Thursday, the rupee traded in a narrow range and settled lower by 3 paise at 83.93 against the American currency."Despite the dollar index reaching a recent low, the Indian rupee remains steadfast, showing little signs

of strengthening. This resilience can be attributed to the central bank's deliberate interventions, aimed at stabilizing the USDINR around the 83.90-95 range," CR Forex Advisors MD-Amit Pabari said.

Festive offer

Meanwhile, the dollar index, which gauges the greenback's strength against a basket of six currencies, was down 0.15 per cent to 101.35 points.

Brent crude, the global oil benchmark, was 0.12 per cent up at USD 77.31 per barrel in futures trade, "In the near term, the rupee is expected to trade within a narrow range, with an upside limit around 83.80 and support around 84.00," Pabari added.The domestic equity market witnessed heavy volatility in morning trade, the 30-share BSE Sensex which opened on a positive note was later trading 13.2 points, or 0.02 per cent down, at 81,039.99 points.

The Nifty also witnessed similar movement, it opened on a higher note, but soon pared the gains to trade 8.25 points, or 0.03 per cent lower at 24,803.25 points.Foreign Institutional Investors (FIIs) were net buyers in the capital markets on Thursday as they purchased shares worth Rs 1,371.79 crore, according to exchange data.On the domestic macroeconomic front, the minutes of the last Monetary Policy Committee (MPC) released by the RBI on Thursday noted that the calibrated increase in policy repo rate by 250 basis points since May 2022 and subsequent change of stance to the withdrawal of accommodation have facilitated gradual disinflation over 2022-23.

Sensex, Nifty open flat as global markets cautious; RVNL, IRFC gain

New Delhi Benchmark stock market indices opened lower on Friday, tracking a pause in global equities rally ahead of US Federal Reserve Chairman Jerome Powell's address.The S&P BSE Sensex was down 0.01% at 81,041.84 at 10:39 am, while the NSE Nifty50 rose 4.25 points to 24,815.75.

All the other broader market indices saw mixed trends, with some gaining and others in the red.

However, most of the Nifty sectoral indices fell during the session. The only exception was Nifty Auto, which was up nearly 1%.

The top five gainers on the Nifty50 were Bajaj-Auto, Coal India, Hero MotoCorp, Tata Motors and Hindalco.On the other hand, the top losers were Grasim, LTIM, Titan, Asian Paints and Wipro.Among individual stocks, shares of railway firms such as RVNL and IRFC rose sharply in early trade, with reports suggesting a possibility of a short-term rally.

Dr. V K Vijayakumar, Chief Investment Strategist,

Geojit Financial Services, said, "Market is witnessing significant sectoral churning. The PSU stocks rally which gave excellent returns in recent months is losing steam. For PSU banking stocks, the turnaround story which took the PSU banks from losses of Rs 87000 crores in FY 2018 to profits of Rs 1.41 lakh crores in FY 2024 is over. But the valuation of this segment is still attractive."Defence and many railway stocks have good growth prospects but the valuations in most cases had run ahead of fundamentals, warranting a correction which has been happening recently. Money is moving into private sector financials where valuations are fair and attractive in this market which doesn't have valuation comfort. This churning is fundamentally sound," he added."Globally the market's focus today will be on Jerome Powell's comments at Jackson Hole on the economy and the possible rate cut trend. Powell is likely to sound dovish indicating a rate cut in September."

Internship portal in the works, will match skill sets with opportunity

New Delhi A new portal is in the works to enable youth to apply for internships directly with the country's top 500 companies under a special package announced in the Budget. The portal will facilitate matching of skill sets of the applicants with the type of internship opportunities provided by the companies.The Ministry of Corporate Affairs (MCA) will announce the guidelines for the internship scheme over the next two weeks, following which the portal will be made active for the prospective applicants, officials involved in the exercise said."The idea is not to upload any existing database of the country's youth on the portal, because some may not want to opt for this internship scheme. Instead, the companies will list out their internship opportunities and these will get matched with the information provided by the applicants, enabling a free flow of information on the portal," a senior government official told The Indian Express.The portal is expected to be functional after the guidelines for the scheme are finalised by the MCA. The ministry is in discussion with the companies, the official said.In the Union Budget for 2024-25 presented by the NDA government on July 23, Finance Minister Nirmala Sitharaman had announced the Prime Minister's Package for Employment and Skilling with an overall outlay of Rs 2 lakh crore. The government is keen to ensure that those at the margins, especially those less skilled and less employable, are able to make the most of this internship scheme.As part of the package announced in the Budget, internships are to be provided to 1 crore youth by India's top 500 companies over the next five years. "They will gain exposure for 12 months to real-life business environments, varied professions and employment opportunities. An internship allowance of Rs 5,000 per month along with a one-time assistance of Rs 6,000 will be provided. Companies will be expected to bear the training cost and .

Sebi imposes 5-year trading ban on Anil Ambani, fines him Rs 25 crore

In its 222-page final order, Sebi revealed that Anil Ambani and RHFL's top executives orchestrated a fraudulent scheme to divert funds from RHFL under the guise of loans to entities connected to him.

New Delhi. Markets regulator Securities and Exchange Board of India (Sebi) has barred industrialist Anil Ambani and 24 other entities, including former key officials of Reliance Home Finance from the securities market for five years for diversion of funds from the company.

Sebi has imposed a Rs 25 crore penalty on Ambani and banned him from any association with the securities market, including serving as a director or Key Managerial Personnel (KMP) in any listed company or intermediary registered with the regulator, for a period of five years.Additionally, the regulator barred Reliance Home Finance from the securities market for six months and fined it Rs 6 lakh.In its 222-page final order, Sebi revealed that Anil Ambani and RHFL's top executives orchestrated a fraudulent scheme to divert funds from RHFL under the guise of loans to entities connected to him.Despite the RHFL Board of Directors issuing firm directives to halt such lending practices and regularly reviewing corporate loans, the management disregarded these instructions.Sebi concluded that the fraudulent scheme was executed by Ambani and the KMPs of RHFL, funnelling funds through credit-unworthy conduit borrowers, all of whom were linked to Ambani himself.

The market regular also said that Anil Ambani leveraged his position as the "chairperson of the ADA group" and his indirect shareholding in RHFL's holding company to execute this scheme.

Sebi noted that loans worth hundreds of crores were approved for companies with little to no assets, cash flow, or revenue, suggesting a deliberate intent behind these loans. Most of these borrowers defaulted, resulting in RHFL's own debt default and its eventual resolution under the RBI Framework. This left public shareholders, including over 9 lakh investors, with significant losses.

RHFL's share price, which stood at Rs 59.60 in March 2018, plummeted to Rs 0.75 by March 2020 as the fraud unravelled.Sebi imposed penalties on 24 restrained entities, including former RHFL officials Amit Bapna, Ravindra Sudhalkar, and Pinkesh R Shah, who played key roles in the fraud. Ambani was fined Rs 25 crore, Bapna Rs 27 crore, Sudhalkar Rs 26 crore, and Shah Rs 21 crore.It also imposed Rs 25 crore fines on several other entities, such as Reliance Unicorn Enterprises, Reliance Exchange Next Ltd, Reliance Commercial Finance Ltd, Reliance Cleangen Ltd, Reliance Business Broadcast News Holdings Ltd, and Reliance Big Entertainment Pvt Ltd.

These entities were either recipients of the siphoned funds or intermediaries in the fraudulent diversion of RHFL's resources.The ruling comes after Sebi's interim order from February 2022, which had already barred RHFL, Anil Ambani, and three others from the securities market for allegedly siphoning off funds from the company.

Champai Soren's new outfit, BJP's benefit

Champai Soren's new political outfit is likely to benefit the BJP more than him. The saffron party would prefer the former Jharkhand CM to focus on the Kolhan Division and eat into Hemant Soren's JMM vote bank.

New Delhi: For three days in Delhi, camera crews were stationed outside a posh hotel, waiting for a glimpse of former Jharkhand Chief Minister Champai Soren. A meeting with Union Home Minister Amit Shah and top Bharatiya Janata Party (BJP) leaders was anticipated. However, Champai Soren left Delhi without any publicised meetings with the BJP.When he returned to his home constituency, Saraikela in Jharkhand, the "Tiger of Kolhan" announced that "a new chapter of his life has started" and hinted at either launching a new political outfit or joining hands with a "sathi" (friend) in this new journey.owever, a source clos to Champai Soren told India Today that the former Chief Minister would soon launch his new faction.

"He will be launching his own faction ahead of the Jharkhand Assembly polls," top sources said. They further added that Soren returning to the Jharkhand Mukti Morcha's (JMM) fold is out of the question.Notably, those close to Champai Soren maintain that the JMM stalwart-turned-rebel "doesn't intend to break up the JMM for his new faction".However, sources indicated that

certain JMM leaders are in touch with Champai Soren. Rebels like MLA Chamra Linda could be part of the new faction, sources claimed.

WHY BJP WANTS THE 'TIGER' FOCUSED ON KOLHAN

Champai Soren is the most senior tribal leader in the JMM after party patriarch Shibu Soren. His stature within the JMM was evident when Hemant Soren stepped down as Chief Minister of Jharkhand due to an ED arrest, and Champai Soren was chosen over his cabinet colleague Joba Majhi to assume the office.After his release from Ranchi jail on July 4, Hemant Soren returned to the CM office, and Champai Soren was accommodated in the Jharkhand Cabinet as the new Education Minister.

However, this didn't sit well with the 'Tiger of Kolhan'. Now, Champai Soren reiterates that he had decided to start the new adhyay (chapter) of his life on July 3.

Champai Soren insists that he will soon launch his own party or join hands with a "friend" in his journey to "build the Jharkhand of his dreams".What would be a better proposition for the BJP in this scenario? Having a former Jharkhand Chief minister join the BJP or assisting him in creating a new outfit?The obvious answer would be: a new political outfit led by the JMM rebel, with the BJP not forging any alliance with this new faction in the upcoming 2024 Jharkhand polls.Kolhan division has 14 assembly segments. The BJP was crushed by the Hemant Soren-led Mahagathbandhan in the 2019 elections in this division. The saffron party failed to open its tally in Kolhan, and its sitting Chief Minister Raghubar Das faced a humiliating defeat at the hands of BJP rebel Saryu Roy.

Through this tribal-dominated belt, the JMM cemented its victory in the 2019 assembly polls. Despite the Modi wave and the Ram Mandir wave, Hemant Soren's JMM won 11 of the 14 assembly segments, and two were clinched by the Congress. These numbers ensured that the JMM recorded its best-ever electoral performance in Jharkhand polls.

Champai Soren's stronghold in the Kolhan belt has a long history. He is often hailed as a leader of the working classes who fought for the cause of a separate Jharkhand state under 'Guruji' (what Shibu Soren is popularly called). He takes pride in having ensured that over 10,000 youths from local villages in this belt secured jobs in industrial establishments like the Tata Group.If Champai Soren enters the 2024 electoral fray alone, the BJP is expected to gain more. With limited resources, the former Chief Minister would likely focus on Kolhan division assembly seats.While one might hope that Champai Soren could retain the Saraikela assembly segment and possibly win one more assembly seat for his new outfit, it would come at the cost of the JMM.Moreover, Champai Soren could aim to deliver what Chirag Paswan's LJP faction did to the Janata Dal United (JDU) in Bihar in 2021. The LJP fought alone, and its candidates are believed to have eaten into the JDU vote bank. While Chirag Paswan's party managed to win only one seat, it played a crucial role in the defeat of the JDU on several assembly seats.

Assam girl, 14, gang-raped, found on road in semi-conscious state

New Delhi: A 14-year-old girl was allegedly gang-raped by three men in the Nagoan district of Assam. The survivor was rescued by police in a semi-conscious state on a road in Dhing area of the district on Thursday.

The police rescued the survivor after receiving a tip off from a passerby. The accused are yet to be identified.The rescued minor girl has been admitted to Dhing medical unit in Nagoan district of the state. The Student Union has called a Bandh in the area today in lieu of the incident.

Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma strongly condemned the incident, describing it as a "crime against humanity". Taking to X, the Chief Minister expressed his outrage over the incident and vowed to bring the accused to justice."The horrific incident at Dhing, involving a minor, is a crime against humanity and has struck our collective conscience. We will NOT SPARE anyone & BRING the perpetrators to JUSTICE," Sharma wrote.He also added that he has directed the Director General of Police (DGP) of Assam, to visit the site of the crime and ensure swift and decisive action against those responsible. "I've directed DGP Assam Police to visit the site and ensure swift action against such monsters," he added.

Kolkata rape accused has 'animal-like instinct', showed no guilt: Psychoanalytic test

New Delhi: The psychoanalytic profile of Sanjay Roy, the prime accused in the Kolkata rape-murder case, indicated that he was addicted to pornography, had "animal-like instincts" and showed no remorse for the crime, an officer of the Central Bureau of Investigation (CBI) said on Thursday.The CBI on August 18 had ordered experts from CFSL to carry out a psychoanalytic profile of Roy. A civic volunteer with Kolkata Police, Roy was arrested the day after the body of the 31-year-old trainee doctor was found at the state-run RG Kar Medical College and Hospital on August 9.The man showed no repentance and narrated the entire episode giving every minute detail without hiccups. It

appeared that he had no remorse," the CBI official told news agency PTI on Thursday.

Before the investigation was handed over to the CBI by the Calcutta High Court, the local police had found a trove of pornographic content on the mobile phone seized from Roy.The CBI officer also highlighted that both technical and scientific evidence "very much support" that Roy was present at the crime scene.Based on the CCTV footage collected from the hospital, Roy could be seen near the chest department ward at around 11 am on August 8.Sources had revealed earlier to India Today that Roy also visited a 'red light area' in North Kolkata after midnight on August 8. He was also intoxicated and later asked a random woman for her nude photograph."Footage showed him entering the same building again at around 4 am on August 9. Certain technical and scientific evidence corroborated that," the officer added.In his interview with PTI, the officer refused to divulge any information about the DNA tests conducted on Roy or comment on the gang rape rumours.

Roy's residence in Bhowanipore was also visited by CBI officers where they spoke with his family, neighbours and his colleagues in the Kolkata Police force.

Exclusive: Why CBI wants polygraph test on 3 Kolkata hospital doctors, staffer

New Delhi: New details have emerged in the ongoing investigation into the rape and murder of a trainee doctor at RG Kar Hospital in Kolkata. The CBI will conduct polygraph tests, also known as lie detector test, on four hospital employees to determine if they were involved in the crime, sources said.The victim, a postgraduate trainee (PGT) doctor, was found dead in a seminar hall at the hospital on August 9. The accused, Sanjoy Roy, a civic volunteer with the Kolkata Police, was arrested the day after the incident.According to sources, Roy entered the seminar hall around 4:03 a.m. while the victim was sleeping. He allegedly raped and killed her before leaving the hall around 4:40 a.m. The victim is believed to have died between 4:15 AM and 4:40 AM.

The CBI is conducting polygraph tests on two first-year PGT doctors whose fingerprints were found in the seminar room. They were on duty with the victim the night of the incident and had dinner together before retiring to the seminar room.Also undergoing polygraph tests are a house staff member who was seen on CCTV footage going to the third floor from the first floor emergency, and an intern who was on the same floor and interacted with the victim before she went to rest.While medical reports, including DNA evidence from the victim's body, do not conclusively link these four individuals to the crime, the CBI wants to determine if they played any role in tampering evidence or were involved in a conspiracy, sources said.

The sequence of events on the fateful night, according to statements from the four individuals, is as follows:The two first-year trainee doctors had dinner with the victim around 12 a.m. and then watched the Olympics Javelin Final in the seminar room.The three decided to rest in the seminar room, as the sleep room was being used for a polysomnography test.The first-year doctors went to the sleep room after the test ended, around 1:30-2:00 a.m., in case they needed to attend to patients.The victim remained in the seminar room.The house staff member ws on duty in the emergency on the first floor. He went to the third floor around 2:45 a.m. and returned between 3:30 and 3:45 a.m.The intern was in a separate room on the third floor.According to the statements, none of the four heard anything from the seminar room.The victim's body was discoered by the first year doctor the following morning, who alerted hospital authorities.

First parliamentary committee meet on Waqf bill features heated debates

New Delhi: The first sitting of the Joint Committee of Parliament on the Waqf Bill took place on Thursday with heated exchanges with decibel levels remaining high as members argued for and against the contentious proposal.The proposed bill aims to centralise the regulation of the numerous Waqf boards across the country, allowing a non-Muslim chief executive officer and at least two non-Muslim members to be appointed by the state government to the Waqf boards at the state level.

The 31 member committee met in parliament annexe and deliberated over the bill with each member sharing their viewpoint. The opposition members made it clear that they were against the proposal and that it should be rejected.

There was heated debate in the meeting as members were upset with the presentation by the Ministry of

Minority Affairs, finding it unsatisfactory."The secretary had not come prepared, and the presentations lacked details of the history, the present and why the bill was needed at l," said one member.AIMIM chief and MP Asaduddin Owaisi submitted a fourteen-page letter in which he cited arguments against the background note circulated on the bill. He demanded his dissent b included in the final report."All members were in agreement that the government had put up a shoddy presentation and that temperatures went soaring," another member added.The opposition's main concern to the bill was on the grounds that the basic nature of the bill was against the spirit of equality, freedom of religion and right to form and maintain religious institutions.

Other reservations about the bill included the level of state intervention that dilutes the powers of the Waqf Board. Another concern pertained to giving the collector over-arching powers to adjudicate matters regarding Waqf properties. As one of the most over burdened functionaries in the administration, it was the consensus that the collector would not be able to spare the time to deal with Waqf disputes.

Army's swift efforts save 27 lives after bus falls into gorge in Ladakh

New Delhi: The Indian Army personnel, deployed near Ladakh's Durbuk, provided crucial assistance and saved as many as 27 lives after a bus, taking staff members of a school to a wedding function, fell into a gorge on Thursday.

At least seven people died and several others, including three children, were injured in the accident.The accident was noticed by the Army personnel, who were deployed in the area, following which they rushed to the scene and initiated the evacuation of the passengers.

According to a statement by the Army, as many as 27 passengers were rescued and sent to nearby medical facilities. The injured were initially evacuated to the Military Hospital and Primary Health Centre at Tangste, where they received urgent medical attention, the statement said.The Army deployed helicopters to move 22 injured people to Military Hospital in Leh.

As many as 14 sorties were conducted by the Army's Advanced Light Helicopters (ALH) and Cheetal Helicopters to airlift the injured passengers, the statement added.Following initial examination and treatment, 20 of the injured were transferred to Sonam Norbu Memorial (SNM) Hospital in Leh for specialised care.

Manipur High Court Cancels 'Default Bail' Granted To Man Charged Under UAPA In "Republic Of Kukiland" Case

Mark Thangmang Haokip was arrested on May 30, 2022 on charges of waging war against India and working against the nation to create an "independent Government of the People's Democratic Republic of Kukiland", according to the chargesheet

Imphal/New Delhi: A special court's order granting 'default bail' to an accused charged under the stringent anti-terror law UAPA has been set aside by the Manipur High Court. The high court on Thursday rejected the accused's claim that the chargesheet against him was "incomplete".'Default bail' refers to the relief available to an accused if officials do not complete investigation within a specified period.A special court of the National Investigation Agency (NIA) in Manipur's capital Imphal had granted 'default bail' to the accused Mark Thangmang Haokip, 39, on the grounds that the investigators did not take the prosecution's sanction while filing the chargesheet, thus making it "incomplete."Mark Thangmang Haokip was arrested on May 30, 2022 on charges of waging war against India and working against the nation to create an "independent Government of the People's Democratic Republic of Kukiland", according to the First Information Report (FIR) and the chargesheet. He conspired with others to this end and had also started collecting funds, the chargesheet stated.Mark Thangmang Haokip called himself "president" of the "People's Democratic Republic of Kukiland" in a statement on October 23, 2019 which appealed to "neighbouring countries" to

"respect the sovereign rights of the Kukis."While the website 'kukigovt.com' and 'KukiGovt" social media handles are no longer active, in its communication to the public it described itself as "a human rights based non-violent political government of the Kuki nation."

High Court Cites Supreme Court Judgment

The Manipur High Court, however, said chargesheet filed without the prosecution's sanction is not necessarily an "incomplete" chargesheet, citing an order of the Supreme Court on May 1, 2023 in a NIA case against Punjab resident Judgebir Singh who faced a terror-related case.The high court bench of Chief Justice Siddharth Mridul and Justice A Guneshwar Sharma said the Imphal special court (NIA) judge "erred grossly" in granting 'default bail' to the accused, who faced charges under the stringent Unlawful Activities (Prevention) Act, or UAPA."It is now a settled proposition of law that chargesheet filed without prosecution sanction order cannot be treated as an incomplete chargesheet... We are of the view that the learned special judge (NIA), Imphal West, erred grossly in holding that the subject chargesheet filed without prosecution sanction order from the competent authority is an incomplete chargesheet and the accused is entitled to be released on bail," the Manipur High Court said.The high court said the chargesheet was submitted on November 25, 2022, the 'default bail' application was filed on March 18, 2023, and the default bail was granted on March 28, 2023.

At DNC, Kamala Harris to accept nomination in biggest speech of her career

Kamala Harris will be the first Black woman and first person of South Asian descent to accept a major party's presidential nomination, and if elected, she would be the first female US president.

Chicago, Vice President Kamala Harris will tell voters they have a chance to chart a "new way forward" as Americans this November, as she looks to introduce herself to voters and prosecute her case against Republican Donald Trump Thursday night as she accepts her party's nomination at the Democratic National Convention.Harris' address in Chicago caps a whirlwind eight weeks in American politics and manifests the stunning reversal of Democratic fortunes just 75 days until Election Day. Party leaders, who had publicly despaired over President Joe Biden's candidacy after his disastrous debate against Trump, were jubilant both at the historic nature of Harris' candidacy and their buoyed hopes for this November."With this election, our nation has a precious, fleeting opportunity to move past the bitterness, cynicism, and divisive battles of the past," Harris will say, according to excerpts released by her campaign. "A chance to chart a New Way Forward. Not as members of any one party or faction, but as Americans."Harris will be the first Black woman and first person of South Asian descent to accept a major party's presidential nomination, and if elected, she would be the first female US president. And when she takes the stage, she will be looking out across a sea of female delegates and Democratic supporters wearing white — the colour of women's suffrage — the movement that culminated

with American women securing the right to vote in 1920.A festive mood filled the United Center before Harris appeared onstage, with a packed audience including running mate Tim Walz dancing and singing along to a mix of pop and classic rock. Two of Harris' young grandnieces were brought onstage by actress Kerry Washington to remind the convention how to correctly pronounce her first name. At the girls' direction, one side of the arena shouted "comma" and the other "la."Just a month after Biden ended his reelection bid and endorsed her to replace him atop the Democratic ticket, Harris will look to make the most of her chance to define herself to voters on her own terms before an audience of millions.Harris will share her background rising from a middle-class family to protect others as a prosecutor, contrast her "optimistic" vision with Trump's "dark" agenda and evoke a sense of patriotism, according to a campaign official who spoke on condition of anonymity to discuss sensitive speech preparations.Harris spoke briefly to the convention on Monday, when she thanked Biden and celebrated his record as president, and again on Tuesday, when the beginning of her rally in Milwaukee was streamed into the convention hall after Democrats reaffirmed their nomination of her with a state-by-state roll call.Among others who will speak before Harris on Thursday were Michigan Gov. Gretchen Whitmer, North Carolina Gov. Roy Cooper, civil rights leader Al Sharpton and Randi Weingarten, president of the American Federation of Teachers.

News box

Australia's new 'right to disconnect' law allows 'ignoring' bosses after work

Sydney. Australian employees will from Monday have the right to ignore their bosses outside working hours thanks to a new law which enshrines the "right to disconnect."

The law, which passed in February, protects employees who refuse to monitor, read or respond to contact from their employers outside work hours.Similar laws giving employees a right to switch off their mobile devices are already in place in France, Germany and other countries in the European Union.As the law moved through parliament earlier this year it drew criticism from employer groups who called the legislation rushed and flawed.The law allows for certain circumstances where an employee's right to refuse is unreasonable, depending on their role, the reason for the contact, and how it is made, among other factors.

Six-year-old Vietnamese boy rescued alive after five days lost in dense forest

World. A six-year-old boy who was missing for five days has been found deep in a forest in Vietnam.Dang Tien Lam, a resident of Van Yen district in Yen Bai province, disappeared on August 17 while playing in a stream with his nine siblings.Lam was discovered on Wednesday by a local farmer, Ly Van Nang, who found the boy in a weakened state and unable to stand. Lam was located sitting among cassava bushes approximately 6 km from where he had gone missing.

"I'm so tired, I can't stand up. Please carry me," Lam reportedly said, according to 52-year-old farmer Ly Van Nang, as cited by BBC News.During his ordeal, Lam survived by eating leaves, wild fruits, and drinking stream water.Local authorities had mobilised around 200 people, including police, soldiers, and volunteers, to search for the child.

The intensive search included reviewing CCTV footage to determine if Lam had been abducted. After ruling out kidnapping, rescuers checked streams and even emptied fish ponds to investigate the possibility of drowning.Just before noon on Wednesday, while farmer Ly Van Nang was returning to his tent in the forest for lunch, he heard the child's cries.Nang promptly carried Lam down the hill, where he was reunited with his parents and subsequently taken to a medical facility for a health check-up.

Thailand Plane Crash: All 9 on board believed dead

T**World.** he names of those on board were not immediately available. However, the spokesperson said they included five Chinese tourists from Hong Kong, two Thai female crew and the Thai pilot and co-pilot.

The cause of the crash is not yet known.

According to the reports, Civil Aviation Authority of Thailand said the turboprop plane, a Cessna Caravan C208B operated by the Thai Flying Service Company, had departed Bangkok's Suvarnabhumi Airport at 2:46 p.m. (0746 GMT).Air traffic control lost radio and radar contact with the aircraft 11 minutes later, when it was at estimated 35 kilometers (22 miles) southeast of the airport.It had been headed to Trat, a coastal province about 275 kilometers (171 miles) southeast of the Thailand's capital, AP reported.Video from the scene showed highly fragmented pieces of the plane in water in the middle of a wooded area. A rescuer could be seen in muddy water up to his chest.

The Chachoengsao provincial spokesperson said further searches were going slowly because it was already dark and the rising tide had flooded the crash site with more water.

11 cops killed, several injured in rocket attack in Pakistan's Punjab

According to officials in Pakistan, dacoits armed with guns and rocket-propelled grenades ambushed a police convoy in Punjab province, killing at least 11 officers and wounding others.

Lahore At least 11 policemen were killed and several injured when outlaws attacked them with rockets in Punjab province of Pakistan on Thursday, police said.Many police personnel were also taken hostage in Rahim Yar Khan district, some 400 kilometres from Lahore when two police mobile vans got stuck in a muddy roadway at Machah Point."Meanwhile dacoits (outlaws)

reached there and attacked them with rockets. At least 11 cops were killed in the attack on the spot while some of them were taken hostages and remaining were injured," a spokesperson for the Punjab police said.He added the death toll might increase as the condition of some of the injured was critical.The outlaws managed to flee after the attack.The spokesperson said a heavy contingent of police reached the spot and shifted the injured to Sheikh Zayed Hospital in Rahim Yar Khan following the incident.

Taking strict notice of the incident, Punjab Chief Minister Maryam Nawaz ordered IG Police Dr Usman Anwar to rush to the spot and launch an operation to recover the policemen taken hostage by the outlaws.She said the outlaws' rule in kacha areas (suburbs) of such districts will not be tolerated.

Russian ambassador says US plans to give Ukraine carte blanhe on weapons

Moscow. Russia believes that the United States will at some point remove all restrictions on the use of weapons supplied to Ukraine, the RIA news agency cited Russian ambassador to the U.S. Anatoly Antonov as saying on Friday."The current administration behaves like a person who extends one hand and holds a dagger behind their back with another one," Antonov said, describing Washginton's recent comments about Kyiv not being allowed to use U.S. weapons for strikes deep into Russian territory as "goading".

"They are, essentially, laying ground (for a decision) to simply remove all the

existing restrictions at a certain point, without much thought."

The United States has provided Ukraine with more than $50 billion worth of military aid since 2022, but has limited the use of its weapons to Ukrainian soil and counterfire, defensive crossborder operations.Antonov said serious dialogue with the US would only become possible if it ends its "hostile" policy towards Russia, which includes the support of Ukraine and the implementation of sanctions against Moscow.Antonov said a meeting between Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and U.S. Secretary of State Antony Blinken appeared unlikely during the United Nations General Assembly session next month.He also said Moscow had no plans to interfere in the US presidential elections.

Bangladesh has revoked diplomatic passport of ex-PM Hasina: Government

DHAKA. Bangladesh's interim government revoked the diplomatic passport of ousted premier Sheikh Hasina on Thursday, after she fled a student-led uprising earlier this month.

The interior ministry said in a statement that Hasina's passport, as well as those belonging to former government ministers and ex-lawmakers no longer in their posts, "have to be revoked".More than 450 people were killed -- many by police fire -- during the weeks leading up to Hasina's ouster, as crowds stormed her official residence in Dhaka.A United Nations team arrived in Bangladesh on Thursday to assess whether to investigate alleged human rights violations committed during protests that ended Hasina's iron-fisted 15-year rule.

"The former prime minister, her advisers, the former cabinet and all members of the dissolved national assembly were eligible for diplomatic passports by virtue of the positions they held," the ministry said in a statement."If they have been removed or retired from their posts, their and their spouses' diplomatic passports have to be revoked."Hasina's government was accused of widespread abuses, including the mass detention and extrajudicial killing of political opponents.Dhaka's new authorities said that Hasina, and other former top officials during her tenure, could apply for a standard passport, but that thosedocuments were contingent on approval."When the aforementioned people apply afresh for ordinary passports, two security agencies have to clear their application for their passports to be issued," the ministry added.Hasina, who fled to India, was a close ally of Prime Minister Narendra Modi, whose Hindu-nationalist government preferred her over her rivals from the Bangladesh Nationalist Party, which it saw as closer to conservative Islamist groups.While India is hosting Hasina, Modi has also offered his support to the new Bangladeshi leader Nobel laureate Muhammad Yunus, who is heading the caretaker administration.

Yunus has said his administration would "provide whatever support" UN investigators need.

Andrew Tate ordered to be put under house arrest in Romania: Report

A Romanian court has decided internet personality Andrew Tate should be placed under house arrest, his representative said in a social media post on Thursday.

Bucharest, Romania, A Romanian court has decided internet personality Andrew Tate should be placed under house arrest, his representative said in a social media post on Thursday.Prosecutors have requested that Tate be detained for 30 more days after he was among six people taken into custody in an investigation into human trafficking and sexual exploitation.Romanian prosecutors earlier requested that Andrew Tate be detained for 30 more days, the internet personality's representative said on Thursday.The former professional kickboxer and his brother Tristan were among six people detained on Wednesday for an initial 24 hours after Romania's anti-organised crime prosecuting unit DIICOT conducted four home searches in Ilfov county and the Bucharest municipality.He was already indicted in mid-2023 along with his brother and two Romanian female suspects for human trafficking, rape and forming a criminal gang to sexually exploit women, allegations they denied.

"The Tate brothers have been issued a proposal for 30 days preventative arrest by the Romanian DIICOT," Tate's representative said in a statement, adding that a hearing to decide on the detention would be held at 1200 GMT in Bucharest.The representative did not address the fresh allegations against Tate in the statement and did not immediately respond to a request for comment.Before their latest detention the brothers had been subject to a travel ban, under which they were free to travel within Romania but not leave the country.

A self-described misogynist, social

media influencer Tate has gained millions of fans by promoting an ultra-masculine lifestyle that critics say denigrates women.A post on Tate's account on social media platform X said "All they try to do is damage my name with complete bullshit", without specifying who was being referred to.DIICOT said in a statement that it had ordered the detention of six people for crimes including forming an organised criminal group, human trafficking, trafficking of minors, sexual intercourse with a minor and money laundering.It said that it had requested that three of the detained defendants remain in custody while another one be put under house arrest.According to DIICOT, two of the accused used the "loverboy" method, which involves convincing victims that they are in a romantic relationship, to force 34 victims into making pornography which they then sold online for proceeds of over $2.8 million and 887,000 tokens.DIICOT alleges that one of the defendants forced a 17-year-old minor to produce pornography in Britain and Romania creating profits of $1.5 million. It also alleges that the same defendant repeatedly had sexual relations with a 15-year-old victim.

Iceland volcano erupts, spewing lava fountains from Reykjanes peninsula

Copenhagen A volcano in southwestern Iceland erupted on Thursday, the meteorological office said, spraying red-hot lava and smoke in its sixth outbreak since December.The total length of the fissure was about 3.9 km (2.42 miles) and had extended by 1.5 km in about 40 minutes, the Icelandic Met Office, which is tasked with monitoring volcanoes, said in a statement.Livestreams from the volcano on the Reykjanes peninsula showed glowing hot lava shooting up from the ground, their bright-yellow and orange colours set in sharp contrast against the dark night sky."The impact is limited to a localized area near the eruption site. It does not present a threat to life and the area nearby was evacuated," Iceland's ministry for foreign affairs said on social media X.The lava was not flowing towards the nearby

Grindavik fishing town, whose nearly 4,000 residents have been mostly evacuated since November, the Met office said.The eruption took place on the Sundhnukar crater row east of mountain Sylingafell, partly overlapping the other recent outbreaks on the Reykjanes peninsula, in a volcanic system which has no central crater but erupts by opening giant cracks in the ground.Studies had shown magma accumulating underground, prompting warnings of new volcanic activity in the area located just south of Iceland's capital, Reykjavik.The most recent eruption on the Reykjanes peninsula, home to some 30,000 people or nearly 8% of the country's total population, ended on June 22 after spewing fountains of molten rock for 24 days.

The eruptions show the challenge faced by the island nation of nearly 400,000 people as scientists warn that the Reykjanes peninsula could face repeated outbreaks for decades or even centuries.In response, authorities have constructed man-made barriers to redirect lava flows away from critical infrastructure, including the Svartsengi power plant, the Blue Lagoon outdoor spa and the town of Grindavik.Flights were unaffected, Reykjavik's Keflavik Airport said on its web page, but the nearby Blue Lagoon luxury geothermal spa and hotel said it had shut down and evacuated its guests.Volcanic outbreaks in the Reykjanes peninsula are so-called fissure eruptions, which do not usually disrupt air traffic as they do not cause large explosions or significant dispersal of ash into the stratosphere.Iceland, which is roughly the size of the U.S. state of Kentucky, boasts more than 30 active volcanoes, making the north European island a prime destination for volcano tourism - a niche segment that attracts thrill seekers.

NEWS BOX

Umran Malik focused on Duleep Trophy after recovering from Dengue

New Delhi Young India fast bowler Umran Malik is focused on Duleep Trophy after recovering from Dengue. Notably, Duleep Trophy is all set to begin from 5th September 2024 in Anantapur, Andhra Pradesh and M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru.

Malik has been put in Team C alongside Suryakumar Yadav, Ruturaj Gaikwad , Sai Sudharsan, Rajat Patidar among others. Recenly, the 24-year-old opened up on his preparations for the domestic tournament and hoped to do well for his team in the tournament."I am feeling better and now I am fully focused on the preparation of the Duleep trophy at NCA. I hope, I will be doing good in this season for my team," Malik told ANI.Malik didn't have a memorable outing in the previous domestic season picking just four wickets from five matches at an average of 38.50 in the Ranji Trophy 2023-24 for Jammu & Kashmir.

Earlier, he failed to leave his mark in the Syed

Mushtaq Ali Trophy 2023 with six wickets from seven matches at an average of 35.83 and an economy of 8.26. Malik had a forgettable time in the Vijay Hazare Trophy as well, where he went wicketless in the only game he played leaking 68 runs from eight overs.In the Indian Premier League 2024 (IPL 2024), the speedster featured in just one game and was hammered for 15 runs in the solitary over. The 24-year-old has featured in ten ODIs and eight T20Is for India and picked 24 wickets across both formats.

Umran Malik's First Class Numbers

In the 12 first-class matches, Malik has picked 16 wickets from 17 innings at an average of 44.62 and an economy of 4.14. He will be eager to bring his 'A game' to the fore' in the Duleep Trophy and put on match-nning performances for his team.

India are due to tour Australia in November later this year, Malik's pace could prove to be handy on the bouncy surfaces in Australia. However, the speedster will have to prove his mettle in domestic cricket to earn his maiden India Test call up for the blockbuster series.

Tristan Stubbs recalls tough T20 World Cup final loss: Tried my best to forget

South Africa all-rounder Tristan Stubbs revealed that he still has a tough time forgetting his side's tough loss to India in the recent T20 World Cup final and that he doesn't want people to ask him about it.

New Delhi South Africa's promising all-rounder Tristan Stubbs revealed that he is still grappling with the emotional aftermath of his team's narrow defeat to India in the T20 World Cup final on June 29. While the Rohit Sharma-led India side clinched their long-desired title with the T20 World Cup trophy, ending their 13-year ICC trophy drought, the Protreas only saw their own wait extend further. In a recent interaction with IOA, Stubbs revealed that the loss continues to weigh heavily on his mind, making it difficult for him to move on from that day.South Africa had been in a strong position during the final, played at Kensington Oval in Bridgetown, Barbados. With only 26 runs needed from 24 balls and six wickets in hand, the Proteas seemed poised to claim the title. However, a stunning display of death bowling by India's Jasprit Bumrah, supported by Arshdeep Singh and Hardik Pandya, turned the tide, resulting in a heartbreaking 7 run defeat for South Africa.

"T20 WC Final results come up when you don't want it to. I've tried my best to forget, but it's not easy. Someone the other night told us about this and you're like, 'you don't have to tell us, if you feel bad for us'...Some things you don't want to remember," Stubbs told IOA.For Stubbs, the defeat was particularly painful, as he had been instrumental in South Africa's journey to the final. Throughout the tournament, he showcased his hard-hitting abilities, especially when his team needed it most. Batting in the middle order, he managed to

score 196 runs in 11 matches at a strike rate of 101.03, proving his worth as a crucial member of the squad.Despite some impressive performances by the Proteas throughout the tournament, Stubbs explained that it is hard to forget the final match specifically because of how close his side got to their first major trophy. He has expressed that the memory of the loss frequently resurfaces.

Ultimate Table Tennis: Harmeet, Liu power Athlead Goa to win over Jaipur Patriots

Harmeet Desai and Yangzi Liu led Athlead Goa Challengers to victory in the opening tie of IndianOil Ultimate Table Tennis 2024, defeating Jaipur Patriots after a strong comeback in mixed doubles at the Jawaharlal Nehru Indoor Stadium in Chennai.

Chennai. Harmeet Desai bounced back in style after an early setback, partnering Yangzi Liu to success in the mixed doubles round, and helped reigning champions Athlead Goa Challengers beat debutants Jaipur Patriots in the first tie of IndianOil Ultimate Table Tennis 2024 at the Jawaharlal Nehru Indoor Stadium.Goa Challengers won the toss and served first (Men's Singles), with captain Harmeet securing the maiden point of UTT 2024. The Indian star paddler raced into a 5-0 lead and took the first game by a whopping 11-2 scoreline. Cho Seungmin, however, retaliated in the second game, mirroring Harmeet's efforts from the first; the debuting South Korean amassed a massive lead quickly and closed out the game 11-1. The debutant maintained his assertive shots in the deciding game and emerged victorious, 2-1.The indomitable Liu turned the tables around in the second match (Women's Singles), propelling Goa Challengers into the lead by defeating the experienced Suthasini Sawettabut 3-0.Harmeet, Liu, and Suthasini returned to the table and were joined by Ronit Bhanja for the Mixed Doubles. Harmeet and Liu, playing their first tie together, showed incredible coordination to take the first game 11-1. While Suthasini and Ronit recovered in game two, Harmeet and Liu took the match by edging the Jaipur Patriots pair in the deciding game.Ronit faced Athlead Goa Challengers' Mihai Bobocica in the fourth match (Men's Singles), with the Italian making his league bow aged 37. Two-time Olympian Bobocica came from behind to win 2-1, increasing his team's lead to eight points and giving them a tie win.Match five (Women's Singles) between Yashaswini Ghorpade and Nithyashree Mani witnessed the first Golden Point of IndianOil UTT 2024, which the latter claimed en route to securing a 2-1 win.Debutants Ahmedabad SG Pipers will begin their IndianOil UTT 2024 campaign with the first tie of tomorrow's double header against Puneri Paltan Table Tennis at 17:00. Later, PBG Bengaluru Smashers will play hosts Chennai Lions.

Neeraj Chopra's bittersweet reaction after season-best 89.49m in Lausanne

Lausanne. India's javelin ace Neeraj Chopra had a mixed response to his second-place ensuring, and season-best throw of 89.49m throw at the Lausanne Diamond League. What marked a return to action for the Paris Olympics silver-medallist, Neeraj was faced the waves of emotions in his final throw, when he was left initially impressed with his effort, but then was left frustrated after missing his long-desired 90m mark by only a whisker.After missing out on a chance to defend his Tokyo Olympics gold at the Paris Games, Neeraj got straight back into action with his first step being at the Lausanne Diamond League. The 26-year-old wasn't at his best but found the will in the final attempt to produce his best attempt and make it to the second spot after Anderson Peters, who had bested the rest on the day with his 90.61 m throw.Neeraj had started off with a throw of 82.10 and was in 4th spot at the end of round 1. Anderson Peters had taken the early lead at that point with a phenomenal throw of 86.36, while Jakub Vadlejch looked to be struggling initially. The second attempt was

better from the Indian ace as he got back into the top 3 with an 83.21 m throw.The third throw from Neeraj was only 83.13 m as he was now in danger of slipping further down in the rankings. However, he remained in top 4 but the throws still remained well-below his standards.The 5th attempt saw Neeraj get his best throw in and hit 85.58 m to move into the top 3. The final attempt would have only the top 3 and Peters finished off in fine style as he shattered the meeting record with 90.61 m throw. Neeraj would then produce his season best with an 89.49 m throw and Weber to the second spot.leapfrog

One could hardly guess from Neeraj's reaction, that his final throw at Lausanne was also the second-best throw of his entire career.

Paulo Dybala rejects big-money Saudi Pro League move and commits to AS Roma

New Delhi Argentinian attacking midfielder Paulo Dybala has reportedly rejected what was speculated to be a big-money move to Saudi Pro League side Al Qadisah in favor of staying with Serie A club AS Roma. The proposed transfer, speculated to be worth €75 million over three years, has been the subject of intense speculation. However, in a surprising last-minute decision, Dybala chose to stay in Italy, has seemingly put an end to weeks of speculation about his future.

Dybala's situation has been a hot topic in recent weeks, particularly after he trained separately from the Roma squad and missed their Serie A opener against Cagliari. These developments had led many to believe that a move to Saudi Arabia was imminent. However, Dybala's decision to remain with Roma appears to be firm, much to the delight of the club's supporters.Adding to the speculation was a recent Instagram post by Dybala, in which he shared a photo with the

caption, "Thank you Rome...See you on Sunday." This message has been widely interpreted as confirmation that he will remain with the Giallorossi, further quashing rumors of a departure to Saudi Arabia.Since joining Roma from Juventus in 2022, Dybala has become a cornerstone of the team, scoring 34 goals and providing 18 assists across 78 appearances. His performances and dedication have made him a beloved figure amongst Roma fans, who had vocally expressed their desire for him to stay with protests in front of the club's training ground over the past few days.

The decision to reject Al Qadisah's offer, despite its financial allure, underscores Dybala's commitment to Roma. As he enters the final year of his contract, which includes an automatic extension if he plays at least 15 official matches this season, Dybala is set to continue as a key player for the club.

Shreyas Iyer offers his seat to Rohit Sharma at Ceat Cricket Rating Awards

India batter Shreyas Iyer was spotted offering his seat to captain Rohit Sharma in a heart-warming gesture at the Ceat Cricket Rating Awards.

New Delhi Star India batter Shreyas Iyer was spotted giving up his seat for captain Rohit Sharma at the Ceat Cricket Rating Awards event held in Mumbai on Tuesday, August 21. Notably, several big names of Indian and world cricket were felicitated at the event.

India captain Rohit Sharma was bestowed with the honour of Men's international Cricketer of the Year for his outstanding leadership and prolific run with the bat in the previous year. While many big names of the cricketing fraternity took the limelight at the star-studded event, Shreyas Iyer won people's hearts with his heartwarming gesture for the India skipper.In a viral video, Iyer can be seen getting up from his seat and offering it to Rohit which even left the India captain amused. However, the opening batter made him sit in his place and sat one row behind exhibiting great camaraderie between the two.Apart from Rohit, Shreyas Iyer was also honoured at the event for Outstanding Leadership in IPL. The 29-year-old led KKR to their third title win after 10 years beating SRH in the final. Virat Kohli was also adjudged ODI batter of the year. The right-handed batter scored 1377 runs from 24 innings at an average of

72.47 and a strike rate of 99.13 with six hundreds and eight fifties.The 35-year-old also had a record-breaking campaign at the ODI World Cup 2023 scoring a massive 765 runs from 11 innings at an average of 95.62 and a strike rate of 90.31 with three hundreds and six fifties.

Mohammed Shami bags ODI bowler of the Year awardFast bowler Mohammed Shami was adjudged Men's ODI bowler of the year for his exploits 50-over format throughout the year. The right-arm speedster finished as the highest wicket-taker of the ODI World Cup 2023 with 24 wickets to his name from just seven innings at an average of 10.70 and an economy of 5.26.Meanwhile, former India head coach Rahul Dravid was bestowed with Lifetime Achievement Award. Ravichandran Ashwin, Harmanpreet Kaur, Shafali Verma, Yashasvi Jaiswal among others were also felicitated at the event.

Chelsea take 2-0 lead over Servette in Europa Conference League qualifier leg-1

Chelsea clinched a convincing 2-0 win over Swiss side Servette in their Europa Conference League qualifier first-leg on August 23, which saw both Nkunku and Madueke get their names on the scoresheet at Stamford Bridge.

Fulham. Chelsea took a significant step toward securing a spot in the group stages of the Europa Conference League with a 2-0 victory over Swiss Super League side Servette on August 22. The win in the first leg of their qualifier at Stamford Bridge has given the Blues a crucial head start in their quest for European competition.In what turned out to be the side's first major win under new coach Enzo Maresca, Chelsea struggled in the first half, failing to gain control over the game both in terms of possession and gameplay. Servette, determined and organised, managed to keep the Premier League side at bay, frustrating the home crowd and stifling Chelsea's attempts to break through.However, the second half saw a dramatic shift in momentum. Just five minutes after the restart, Chelsea finally broke the deadlock when Christopher Nkunku converted a penalty, his fourth goal for the club. The spot-kick, won after a handball in the box, gave Chelsea the lead and the confidence to push forward.As the game progressed, Chelsea began to assert more control, pinning Servette back and creating more opportunities. The breakthrough came again in the 74th minute when Noni Madueke doubled Chelsea's lead, finishing off a well-executed pass from Enzo Fernandez. This goal effectively put Chelsea in a commanding position for next week's second leg, making their path to the group stages much clearer.

The victory was a much-needed boost for Chelsea, especially after a disappointing 2-0 loss to Manchester City in Maresca's debut game as head coach. With this win, Chelsea will head into the second leg with confidence, knowing they have one foot firmly in the group stages of the Europa Conference League, but face Servette again for the second-led on August 30.

Shraddha Kapoor

on Why She Never Worked With SRK, Salman or Aamir: 'I'm Very Clear About...'

Shraddha Kapoor has given several hit films but the actress has never worked with either of the Khans – Shah Rukh, Salman or Aamir. In a recent interview, Shraddha opened up about the same and revealed that she hasn't yet had the opportunity to work with the 3 Khans of Bollywood. Shraddha shared that even though she was offered films with SRK, Aamir or Salman in the past, she could not get on board for several reasons."Many times you are offered a film, but if you feel the character isn't exciting enough or the role doesn't challenge the artiste in you then you let go off that role. I'm very clear about the kind of work that I choose," Shraddha said during a podcast with Shubhankar Mishra, as quoted by IANS.

"I want to be part of good films, engaging films with good stories, work with good directors, and do good work. If the by-product of all of this is the opportunity to work with good actors or huge stars, I'm happy to say yes to it," the actress added.

Meanwhile, on the work front, Shraddha Kapoor is currently enjoying the success of Stree 2. Also starring Rajkummar Rao, Aparshakti Khurana, Abhishek Banerjee and Pankaj Tripathi, the film hit theatres on August 15 and impressed audiences. Directed by Amar Kaushik, Stree 2 sees Rajkummar and Shraddha reprise their roles from the original. The sequel continues the eerie tale in the town of Chanderi, now haunted by a new terror, Sarkata. The townspeople once again turn to Stree for salvation. The film also features several surprise cameos, including Varun Dhawan as Bhediya, who shares a special song with Shraddha Kapoor.

Stree 2 clashed at the box office with Akshay Kumar and Taapsee Pannu's Khel Khel Mein and John Abraham's Vedaa. Despite this, Stree 2 managed to gather audiences' attention. According to Sacnilk, Stree 2 has collected Rs 254.55 Cr (net, early estimates) as of Day 6. The film is charging towards surpassing the lifetime box office collection of Kalki 2898 AD's Hindi version. Stree 2 is likely to beat that record by this weekend.

Tamannaah Bhatia

Exudes Divine Charm As Modern-day Radha In Peach Designer Saree

Tamannaah Bhatia's name is synonymous with not just acting and dancing but with an impeccable styling game as well. The actress keeps redefining fashion and leaves her fans in awe of her ethereal beauty. Recently, Tamannaah shared a video clip, giving a glimpse of her photoshoot. The video shows Tamannaah dropping water on herself from a pitcher. Tamannaah has styled her look on the idea of Radharani- the Hindu goddess of Vrindavan, and she looks ethereal, to say the least. Social media users could also get a glimpse of an actor dressed as Lord Krishna.

Tamannaah Bhatia looked drop-dead gorgeous in a peach designer saree with intricate embroidery patterns; she paired it with a purple blouse. Flaunting her well-toned body for the cameras, she opted for a flawless base with contoured cheeks for the makeup. She accessorised her looks with earrings and maang tika, and left her hair in soft waves. In the caption, she also talked about how as per the Bhagavad Purana, Lord Krishna is the epitome of love.In yet another string of pictures, Tamannaah posed as Radharani waiting for Lord Krishna in Kunjavan. She also held a Mor Pankh for her few photographs, adding further allure to her post. In the caption, she talked about infatuation.

Tamannaah was last seen in the Stree 2 track Aaj Ki Raat. She is now working on a web series, Daring Partners. Created by Mithun Gangopadhyay and Nishant Nayak. The series features Tamannaah, Jaaved Jaaferi, Diana Penty and Nakuul Mehta. With a narrative based on real events, Karan Johar's production house, Dharmatic Entertainment has backed this thriller. Tamannaah Bhatia has several projects in the pipeline which include Ashok Teja's directorial Odela 2. She will also act in the Nawazuddin Siddiqui-starrer film Bole Chudiyan.

Prabhas' Next, Fauji, Introduces Viral Dancer Imanvi Esmail As Female Lead

After the massive success of Kalki 2898 AD and with Raja Saab in the pipeline, superstar Prabhas recently announced his film with director Hanu Raghavapudi. The film will star Mithun Chakraborty, Iman Esmail and Manvi in the prominent roles. The film is produced under the banner of Mythri Movie Makers. The film is tentatively titled Fauji. The much-anticipated project was launched with a puja ceremony in Hyderabad on August 17. Mythri movie makers shared the pictures from the Puja Ceremony which took the internet by storm. It featured the lead pair–Prabhas and Imanvi Esmail posing together for the pictures.The shooting of the film is reportedly set to begin on August 24. With the puja ceremony photos online, the makers have also announced the lead heroine of the film. The makers have roped in dancer and debutant actor Imanvi to feature as the female lead. The Instagram sensation is best known for her dance cover of the Tamil song 'Tum Tum. This comes just a day after it was announced that veteran actors Mithun Chakraborty and Jaya Prada will feature in the film. The fans are buzzing with the excitement of Prabhas's new film.

Imanvi Esmail also shared the snaps from the puja ceremony. She was seen posing with Prabhas and director Hanu Raghavapudi. Take a look at the post,Debutant Imanvi Esmail is a dancer and content creator with more than 8 lakh followers on Instagram. Imanvi Esmail has a huge Indian fanbase. In 2020, her choreography for the song Ramta Jogi from Taal surfaced on the internet creating a massive buzz on social media. In 2023, her other dance performance in the song Tum Tum from Enemy also went viral which helped her to receive several acting opportunities. Iman Esmail is from Los Angeles but presently resides in New Delhi.

Amitabh Bachchan Praises Granddaughter Navya Nanda For Her Women's Welfare Initiatives: 'From Her Own Earnings...'

Amitabh Bachchan returns to captivate audiences with the 16th season of the iconic quiz show, 'Kaun Banega Crorepati'. As a seasoned host, the legendary actor continues to enchant viewers with fascinating stories from his life and career. This season, he shared a touching moment on the show involving his granddaughter, Navya Naveli Nanda.

In a recent episode, contestant Nareshi Meena took the hot seat, revealing her dream of becoming an Investigation Officer. However, her aspirations were challenged when she was diagnosed with a brain tumor during medical examinations. Despite this setback, her determination remained unshaken.

Moved by Nareshi's story, Amitabh Bachchan announced that he would cover the costs of her Proton treatment, commending her strength and bravery. He empathized with her situation, acknowledging the courage it took to share her struggle publicly, and encouraged her to focus on her recovery rather than worrying about the prize money.He remarked, "Badi himmat honi chahiye ek mahila mein. Ek toh sarvajanik roop se yeh baat kehna, iske liye bohot himmat ki zarurat hoti hai. Aur khaas toh jis tarah ki avastha hal uske baare mein baat karna hi mushkil hota hai. Kahin na kahin aapne apne mann ke andar yeh rakh rakha hai, yeh thaan ki main aaj KBC main aayi hoon aur main dhanrashi jeet kar jaungi aur iska ilaaj ho sakta hai. Aapke dhairya ke liye hum aapko dhanyawaad karte hai. Lekin iss or jo aapka dhyaan hai, ab woh apne dimag se hata lijiye aur jo aapka chhipa hua tumour hai, woh bhi nikal jayega(It takes immense courage for a woman to speak openly about such matters. You've held onto the hope that winning on KBC could fund your treatment. Your resilience is admirable, but let go of those worries—your hden tumor will be taken care of too)."The conversation then shifted to Nareshi's work, where she supports women facing domestic violence. She highlighted various schemes by the Rajasthan Government aimed at empowering women.